• वर्ष-2
• अंक-294
रायपुर, मंगलवार 01 अगस्त 2023
• पृष्ठ-8
• मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

कांवड़ियों पर पथराव, नूंह में धारा 144

2 अगस्त तक इंटरनेट बंद, सोहना में भी बवाल, मुख्यमंत्री ने की शांति की अपील

नूंह। सोमवार को एक धार्मिक जुलूस के दौरान कुछ उपद्रवियों द्वारा पथराव करने और कारों में आग लगाने के बाद हरियाणा के नूंह में अराजकता फैल गई। दो पक्षों के बीच पथराव के दौरान भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। तनाव की स्थिति को देखते हुए इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। पुलिस के मुताबिक, नूंह के खेड़ला मोड़ के पास युवकों के एक समूह ने यात्रा को रोक दिया और जुलूस पर पथराव किया। वहीं, मेवात के बाद सोहना में भी उग्र भीड़ ने जमकर हंगामा मचाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना गुरुग्राम के सोहना क्षेत्र के अंबेडकर चौक पर हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जनता से शांति की अपील की है।

नूंह हिंसा पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि वहां पर पर्याप्त संख्या में बल तैनात किया जा रहा है। हमने केंद्र से भी बात की है। हम वहां शांति बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां-जहां पर लोग फंसे हुए हैं उन्हें बचाया जा रहा है। अनिल विज ने कहा कि हम निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगे लेकिन हमारा प्राथमिक काम शांति बहाल करना है। नूंह उपायुक्त ने आज रात दोनों पक्षों की बैठक बुलाई है। नूह में धारा 144 लगाई गई है। नूंह से कांग्रेस विधायक चौधरी आफताब अहमद ने कहा कि हम लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रहे हैं। स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मैंने प्रशासन और पुलिस की ऐसी विफलता कभी नहीं देखी।

पुलिस के अनुसार, बृज मंडल जलाभिषेक यात्रा को नूंह में खेड़ला मोड़ के पास युवकों के एक समूह ने रोका और पथराव करने लगे। खबरों के मुताबिक, जुलूस में शामिल लोगों ने उन्हें रोकने वाले युवकों पर पथराव किया। जलाभिषेक यात्रा को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ ने गुरुग्राम के सिविल लाइंस से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। जुलूस के साथ पुलिस की एक टुकड़ी भी तैनात गई थी। पुलिस ने बताया कि इस झड़प में कुछ लोग घायल हुए हैं, लेकिन निर्धारित संख्या अभी नहीं बताई है। कुछ दावों के मुताबिक, झड़प की वजह बल्लभगढ़ में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया एक कथित आपत्तिजनक वीडियो था। नूंह के थाना प्रभारी हुकम सिंह ने कहा, ''इलाके में हालात स्थिर हैं।

सोहना और तावडू भी तनावपूर्ण

बवाल के बाद पूरे मेवात क्षेत्र में हालत बिगड़ने लगे। सोहना में भी आगजनी की खबर सामने आई तो वहीं तावडू भी इससे अछूता नहीं रहा। उपमंडल के गांव सीलखो में कुछ युवाओं पर हमले की सूचना के बाद पुलिस पहुंची, जहां सरकारी वाहन पर पथराव कर दिया।

इलाके में स्थिति तनावपूर्ण होने पर हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने मुख्य बाजार को बंद करा दिया। जबकि मार्ग के साथ दुकानदारों ने खुद ही बंद कर दिया। पटौदी चौक पर भारी भीड़ जमा हो गई, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों ने पहुंचकर शांति की अपील की। जिसके बाद लोग अपने अपने घरों की तरफ चले गए।

हालांकि कुछ देर बाद ही सोहना मार्ग पर हाउसिंग बोर्ड के समीप एक पुलिस पीसीआर पर हमला हो गया। जिसमें एक पुलिस कर्मी घायल हो गया। नूंह में हुए बवाल के बाद कुछ घायलों को सरकारी अस्पताल में लाया गया। इनमें भी एक की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया।

मणिपुर हिंसा के पीछे नार्को आतंकवाद, सुको ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मणिपुर हिंसा पर एक नई जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें अन्य बातों के अलावा कथित पोस्ते की खेती और नार्को-आतंकवाद की एसआईटी जांच की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि इस पर विचार करना बहुत कठिन है क्योंकि इसमें केवल एक समुदाय को दोषी ठहराया गया। याचिकाकर्ता मायांगलांबम बॉबी मीतेई की ओर से पेश वरिष्ठ वकील माधवी दीवान ने याचिका वापस लेने की मांग की और उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी गई।मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि इस याचिका पर विचार करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यह एक समुदाय पर दोषारोपण करती है। आप अधिक विशिष्ट याचिका के साथ आ सकते हैं। इस याचिका में हिंसा से लेकर नशीले पदार्थों से लेकर वनों की कटाई तक सब कुछ है। पीठ ने कहा कि दीवान ने हाल की हिंसा के लिए सीमा पार आतंकवाद और राज्य में पोस्ता की खेती को जिम्मेदार बताया।

दलील नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और एनएचआरसी के साथ-साथ राज्य सरकार सहित अन्य पक्षों द्वारा दी गई है। पीठ के समक्ष मणिपुर हिंसा के कई पहलुओं से संबंधित अन्य याचिकाएं भी हैं। 3 मई को राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से कम से कम 150 लोग मारे गए हैं और कई सौ घायल हुए हैं।

इन दिनों

✍ विवेकानंद

मोदी के बयान के लिए विपक्ष का हंगामा

मणिपुर में बीते कुछ समय से मैतेई और कुकी समुदाय के बीच एक भीषण हिंसक संघर्ष चल रहा है। यहाँ से हाल ही में दो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का एक वीडियो हमारे सामने आया, जिसने पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया। इस वीडियो ने हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी व्यथित कर दिया और उन्होंने इस घटना को 140 करोड़ भारतवासियों को शर्मसार करने वाला बताया। साथ ही, यह भी आश्वस्त किया कि इस घटना के आरोपियों को किसी भी सूरत में बख़्शा नहीं जाएगा। आज यह एक जगजाहिर तथ्य है कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में मणिपुर, असम से लेकर त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों ने विकास, शांति और समृद्धि के नये आयामों को हासिल किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्द्रीय सत्ता में आते ही 'एक्ट ईस्ट' नीति को हमारे सामने लाया, जिसके माध्यम से उनका प्रयास भारत-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ बेहतर राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों को विकसित करना है। उनके इस प्रयास से कभी शेष भारत से बिल्कुल कटा हुआ महसूस करने वाले पूर्वोत्तर के राज्य आज हमारे विकास के 'प्रवेश द्वार' और 'अष्ट लक्ष्मी' के रूप में अपनी एक विशेष पहचान स्थापित कर चुके हैं। लेकिन, मणिपुर हिंसा जैसी घटनाओं से पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास को लेकर हो रहे सभी प्रयासों पर निश्चित रूप से बेहद नकारात्मक असर पड़ेगा और ऐसी घटनाएं दोबारा न हो हमें यह सुनिश्चित करना होगा। हालांकि, इतने संवेदनशील मुद्दे को लेकर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने जिस प्रकार का रवैया दिखाया है। वह वास्तव में बेहद दु:खद और खतरनाक है। उन्हें यह समझना होगा कि यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस पर किसी प्रकार की राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार यह आरोप लगाते रहे हैं, कि उन्होंने आख़िर ढाई महीने से चल रहे मणिपुर हिंसा को लेकर कुछ कहा क्यों नहीं? वे क्षेत्र का दौरा करने क्यों नहीं गये? विपक्ष के ये सवाल वास्तव में उनकी अज्ञानता और राष्ट्र के प्रति उनकी अनिष्ठा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर की स्थिति पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और उनके दिशानिर्देशों पर शांति स्थापित करने के तमाम प्रयास किये जा रहे हैं। और, सवाल जहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी का है, तो आलोचक जरा स्वयं सोचें कि ऐसे समय में, जब भारत जी-20 की अध्यक्षता कर रहा है और हमारे सामने कई महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समझौते हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान से भारत को लेकर दुनिया में क्या संदेश जाएगा? विपक्ष को यह यथाशीघ्र समझने की आवश्यकता है कि यह पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है और इससे निपटने में हम सक्षम हैं। उन्हें दुनिया के सामने अपने ही देश को छोटा दिखाने का प्रयास बंद कर देना चाहिए।

शराब घोटाला : नोएडा में दर्ज हुई ग़ैर जमानती एफआईआर

रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने नोएडा में रिटायर्ड आईएएस अनिल टूटेजा, सीएसएमसीएल के एमडी रहे अरुणपति त्रिपाठी, आबकारी विभाग के आयुक्त रहे निरंजन दास और कारोबारी अनवर ढेबर समेत पाँच के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई है। ईडी की ओर से दर्ज एफआइआर में वे प्रेडिकेट अफेंस हैं जिनसे ईडी को कार्यवाही का आधार मिलता है।

एफआइआर का आधार होलोग्राम को बताया गया है। ईडी की ओर से दर्ज एफआइआर में उल्लेख है कि, ईडी ने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में मनी लॉँड्रिंग की जाँच करते हुए पाया है कि, इस घोटाले में प्रिज्म होलोग्राफी सेक्योरिटी फिल्मस की अहम भूमिका है। इसे गलत तरीके से

होलोग्राम बनाने का काम दिया गया। इन नक़ली होलोग्राम के ज़रिए घोटाले को अंजाम दिया गया। यह होलोग्राम नोएडा में बने और यह काम शराब सिंडिकेट ने दिया। ईडी ने एफआइआर में उल्लेख किया है कि, प्रिज्म होलोग्राम के संचालक विधू गुप्ता ने ईडी को दिए बयान में छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में होलोग्राम को लेकर अपनी भुमिका स्वीकारी है।

ईडी के लिए एफआइआर जरुरी

ईडी ने शराब घोटाला मामले में कार्यवाही शुरु की थी। ईडी की कार्यवाही का आधार आयकर विभाग का दिल्ली के तीस हज़ारी कोर्ट में दायर परिवाद था। उस परिवाद पर विधिक प्रश्न खड़े हो गए। सेशन जज धीरज मोर ने परिवाद पर लिए गए सीजीएम कोर्ट के फ़ैसले पर रोक लगा दी। इस रोक से ईडी की कार्यवाही पर क़ानूनी सवाल खड़े हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने सेशन जज कोर्ट के फ़ैसले को आधार मानते हुए ईडी को कार्यवाही से रोक दिया और कहा कि, ईडी के पास जब भी प्रेडिकेट अफेंस के साथ एफआइआर मिले वह कार्यवाही जारी करने के लिए हमारी अदालत से अनुमति ले सकती है। सेशन कोर्ट और सीजेएम कोर्ट के खिलाफ आयकर विभाग की याचिका हाईकोर्ट में दायर है, जिस पर आज याने 31 जुलाई को सुनवाई होनी है। लेकिन इस पर हाईकोर्ट का कोई फ़ैसला आता उसके पहले ही ईडी ने सीधे एफआइआर दर्ज कर दिया है। नोएडा में दर्ज एफआइआर में प्रेडिकेट अफेंस है याने वे धाराएँ हैं जिनसे ईडी को मनी लॉँड्रिंग में कार्यवाही का आधार मिलता है।

क्या है शराब घोटाला

ईडी ने छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले से मनी लॉँड्रिंग की जाँच शुरु की है।ईडी का आरोप है कि, राज्य की शराब दुकानों में नक़ली होलोग्राम से शराब सप्लाई की गई। इससे राज्य को दो हज़ार करोड़ से अधिक का नुक़सान हुआ।

रायपुर। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन से आज राजभवन में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राइफेड) के उपाध्यक्ष श्री पवित्र कन्हार ने सौजन्य मुलाकात की। (ट्राइफेड) जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एवं राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष संस्था है। जो देश के आदिवासी वर्ग के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए काम करती है।

प्रमुख समाचार

लालू परिवार को बड़ा झटका करोड़ की संपत्ति जब्त

नईदिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सोमवार को जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की संपत्ति कुर्क कर ली। संपत्तियों में यादव परिवार की दिल्ली और पटना की संपत्ति शामिल है, जिसमें न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक आवासीय घर भी शामिल है। यह तब हुआ है जब सीबीआई ने सोमवार को नौकरी के लिए भूमि घोटाले के संबंध में अपनी नई चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के अलावा बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का नाम लिया है। आरोप पत्र, जिसमें 14 अन्य लोगों के भी नाम हैं, मामले में दूसरा आरोप पत्र है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर आरोप पत्र में आरोप लगाया गया कि तेजस्वी और राबड़ी कथित अपराध के लाभार्थी थे। आरोपपत्र विशेष सीबीआई अदालत में दायर किया गया था। आरोप यह है कि 2004 से 2009 तक यूपीए सरकार में मंत्री के रूप में लालू प्रसाद के कार्यकाल के दौरान मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित विभिन्न जोनल रेलवे में पटना के स्थानापन्न लोगों को नियुक्त किया गया था।

अगले तीन महीने में देश के हर घर तक ऐसे पहुंचेगी कांग्रेस

नईदिल्ली। कांग्रेस ने अगले कुछ दिनों के भीतर केंद्र सरकार को घेरने के लिए एक बार फिर से जनता के उन मुद्दों में से एक मुद्दे को बाहर निकाला है, जिस पर बड़ी रणनीति पार्टी ने बनाई है। पार्टी से जुड़े नेताओं के मुताबिक अगले 90 दिनों के भीतर सभी राज्यों में एक बड़े जन अभियान के माध्यम से डीजल और पेट्रोल पर वसूले जा रहे टैक्स और सरकारी/प्राइवेट कंपनियों को होने वाले मुनाफे के बारे में बताएगी। कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है कि जिस तरीके से उनकी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जनता से जुड़े सीधे मुद्दों को उनके ही बीच में ले जाकर रखा है, ठीक उसी तरह इस मुद्दे को भी वह जनता के बीच में ले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता पार्टी और राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश कहते हैं कि बीते एक साल के भीतर कच्चे तेल की कीमतों में 35 फीसदी की गिरावट हुई है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कोई कमी नहीं हुई है। जयराम रमेश का आरोप है कि केंद्र सरकार डीजल और पेट्रोल के माध्यम से ना सिर्फ मुनाफाखोरी कर रही है, बल्कि जनता को मिलने वाली राहत भी नहीं दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है कि इतनी बड़ी मुनाफाखोरी पर उनकी पार्टी चुप नहीं रहने वाली है।

मणिपुर मुद्दे पर घड़ियाली आंसू बहा रहा विपक्षः सीतारमण

नईदिल्ली। संसद के मानसून सत्र में मणिपुर मुद्दे को लेकर गतिरोध जारी है। विपक्ष दल लगातार मणिपुर पर पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। वहीं, सरकार का भी दावा है कि वह चर्चा को तैयार है। बावजूद इसके मामला शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है। राज्यसभा में सोमवार को मणिपुर के मुद्दे पर सूचीबद्ध अल्पकालिक चर्चा शुरू नहीं हो सकी। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सदन में बयान की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। वहीं, लोकसभा में भी मणिपुर के मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों की तरह गतिरोध बरकरार रहा। विपक्षी दलों के हंगामे के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने विपक्ष के रवैये को लेकर उनपर निशाना भी साधा है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि विपक्ष मणिपुर मुद्दे पर चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहता। आज जब यह मुद्दा संसद में उठा तो विपक्ष चर्चा से भाग गया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के व्यवहार से दुखी हूं। मणिपुर उनके (विपक्ष) के लिए सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है।

अमेरिकी सेना में घुसा चीन का जासूस, तलाश जारी

नईदिल्ली। चीन और अमेरिका के बीच की तनातनी जग जाहिर है। अमेरिका की तरफ से चीन द्वारा जासूसी बैलून भेजे जाने की बात भी कही गई थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि चीन की जासूसी का खतरा अमेरिकी सेना के अंदर तक पहुंच गया है। अमेरिकी सेना अपने रक्षा प्रणालियों की जांच कर रही है। वो इसमें छिपे चीनी मैलवेयर की खोज में लगे हैं। ये मैलवेयर पावर ग्रिड और कम्युनिकेशन सिस्टम में हो सकते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी अधिकारी वर्तमान में देश की रक्षा प्रणालियों के भीतर छिपे चीनी मैलवेयर की खोज कर रहे हैं, जो संभावित रूप से सैन्य संचार और पुन: आपूर्ति संचालन को बाधित कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शीर्ष चिंता यह बनी हुई है कि इस दुर्भावनापूर्ण कोड को बीजिंग द्वारा वाशिंगटन के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, जैसे पावर ग्रिड, संचार प्रणाली और जल आपूर्ति को नियंत्रित करने वाले नेटवर्क में छुपाया गया है जो सैन्य ठिकानों के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसी चिंताएँ हैं कि संघर्ष की स्थिति में, हैकर्स अमेरिकी सैन्य अभियानों में हस्तक्षेप करने के लिए इस मैलवेयर का फायदा उठा सकते हैं।

साइबर-अंतरिक्ष युद्ध क्षमताओं को बढ़ा रहा भारत

नई दिल्ली। सरकार तीन नए थिएटर कमान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। वहीं, सैन्य मामलों का विभाग (डीएमए) अपनी साइबर और अंतरिक्ष युद्ध क्षमताओं को और अधिक विस्तारित और उन्नत करने पर विचार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच साल पहले रक्षा साइबर एजेंसी सहित दो एजेंसियों के गठन को मंजूरी दी थी, ताकि इन डोमेन से खतरों से निपटने के साथ-साथ इस क्षेत्र में भारत की आक्रामक क्षमताओं को भी तैयार किया जा सके। इन एजेंसियों का नेतृत्व सेना के मेजर जनरल रैंक के अधिकारी करते हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया, युद्ध में साइबर डोमेन के बढ़ते इस्तेमाल के साथ डीएमए साइबर एजेंसी को और विस्तारित करने और चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक ताकत रखने की संभावना पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध में साइबर डोमेन का बढ़ता इस्तेमाल देखा जा सकता है और हमारे अपने अनुभव भी हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसी तरह हाल के दिनों में हमारे विरोधियों के बारे में उस डोमेन में कई अंतरिक्ष प्रक्षेपण और अन्य तैनाती की सूचना मिली है। हमें अंतरिक्ष क्षेत्र में भी अपनी क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता होगी ताकि थिएटर कमांडरों को खतरों का आकलन करने और उनसे निपटने में मदद मिल सके।

अमेठी सीट कांग्रेस की झोली में वापस डालने के लिए लड़ सकती हैं प्रियंका

स्वदेश कुमार

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए बंजर मरुस्थल बन गया है। अब यहां ना कांग्रेस की सीटें आती हैं, ना वोट मिलता है। स्थिति यह है कि कांग्रेस यूपी में सोनिया गांधी की एक मात्र रायबरेली संसदीय पर सिमट गई है। कहने को तो गांधी परिवार से ताल्लुक रखने वाली मेनका गांधी और वरूण गांधी भी यूपी से सांसद हैं, लेकिन वह कांग्रेस की जगह भारतीय जनता पार्टी से चुने गए हैं। कांग्रेस से यूपी दूर हुआ तो दिल्ली भी दूर होते देरी नहीं लगी। कभी कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक समझा जाने वाले दलित-अगड़े-पिछड़े और मुसलमान वोटर भाजपा और क्षेत्रीय दलों सपा-बसपा के बीच बंट गए हैं। इसी के साथ गांधी परिवार के लिए यूपी गले की फांस बन गया है ना वह इसे निगल पा रही है ना ही उगलते बन रहा है। वैसे कुछ लोग यह भी कहते हैं यूपी में जिस कांग्रेस को राहुल गांधी ने डुबोया है, उसे प्रियंका गांधी फिर से जीवनदान देंगी। सवाल कैसे तो, कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से गले मिलकर। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक ही गठबंधन का हिस्सा हो गए हैं और अगले वर्ष होने वाला लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे, इससे कांग्रेस को अच्छा खासा फायदा हो सकता है। कांग्रेस जो रायबरेली तक सिमट गई है, वह एक बार फिर अमेठी को जीतना चाहती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी यहां से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे।

कांग्रेस करीब तीन दशकों से यूपी में उभार की उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन उसके हालात सुधरने की बजाए बिगड़ते जा रहे हैं। आज की तारीख में तो न उसके पास संगठन बचा है और

न नेता एवं वोटर। इसके लिए कौन जिम्मेदार है की बात चलती है तो गांधी परिवार ही कुसूरवार लगता है, लेकिन यह बात कहने की हिम्मत पार्टी का कोई छोटा या बड़ा नेता कभी जुटा नहीं पाया। यही वजह है कि कांग्रेस यूपी में गर्दिश में चली गई है। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस के गर्दिश के दिनों को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा गांधी दूर करेंगी। कांग्रेसी कह रहे हैं कि भले ही 2022 के विधान सभा चुनाव में यूपी की प्रभारी रहते हुए प्रियंका वाड्रा कुछ खास नहीं कर पाई हों, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। प्रियंका ने जिस तरह से कांग्रेस को कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में सत्ता दिलाई है, वैसे ही यूपी से दिल्ली के लिए भी वह रास्ता बनायेंगी।

उत्तर प्रदेश की सियासी नब्ज पर नजर रखने वाले कहते हैं कि प्रियंका के प्रति जनता में आकर्षण है। पिछले दिनों प्रियंका ने कहा भी था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा तो वह अमेठी या कहीं से भी चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका अभी चुनावी राज्यों में निरंतर सक्रिय हैं। उम्मीद है कि देर सबेर वह उत्तर प्रदेश में सक्रियता बढ़ाएंगी। लोग प्रियंका गांधी के अंदर उनकी दादी की छवि देखते हैं। उनकी सिर्फ शक्ल ही अपनी दादी से नहीं मिलती बल्कि उनके काम करने का अंदाज भी कुछ वैसा ही है, कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सियासी संग्राम में उतर सकती हैं। जबकि कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की संभावना अभी खत्म नहीं हुई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी रायबरेली व अमेठी में पूरी शिद्दत से जुट गई हैं। गांधी परिवार के लिए अन्य संभावित सीटों पर भी गुणा-गणित शुरू हो गया है।

गौरतलब है कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी पिछले चार लोकसभा चुनाव से रायबरेली से सांसद हैं। पिछले दिनों उनके सियासत से संन्यास लेने की चर्चा शुरू हो गई, लेकिन पार्टी के नेता इस चर्चा को एक सिरे से खारिज कर रहे हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव में भले ही रायबरेली के वोटर दूसरे दलों की ओर कदम बढ़ा दें, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस के प्रति पूरी तत्परता दिखती है। ऐसे में पार्टी रायबरेली से सोनिया गांधी को उम्मीदवार मानकर चल रही है। फिर भी अपरिहार्य स्थिति में सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ने से इंकार किया तो यहां से प्रियंका गांधी उम्मीदवार होंगी। इसी तरह राहुल गांधी का मामला कोर्ट में होने की वजह से प्रियंका को अमेठी से भी दावेदार बनाया जा सकता है।

लाख टके का सवाल यही है कि यह सब होगा कैसे? लब्बोलुआब यह है कि कांग्रेस के लिए यूपी में तभी राह आसान हो सकती है जब उसका पुराना वोट बैंक वापस आता है, जो होता दिख नहीं रहा है, ऐसे में उसे समाजवादी पार्टी से गठबंधन से ही यूपी में सियासी जीवनदान मिल सकता है। समाजवादी पार्टी 10 से लेकर 15 सीटें तक कांग्रेस के लिए छोड़ सकती है।

11 मांगो पर किसान सभा की मांग पर अधिकारी पहुंचे गेवरा

- 4 घंटे चली वार्ता के बाद किसान सभा ने कहा आश्वाशन नहीं परिणाम चाहिए
- बिलासपुर से पहुंचे अधिकारियों को किसान सभा ने सीएमडी के नाम ज्ञापन सौंप कर मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी

कोरबा। छत्तीसगढ़ किसान सभा के नेतृत्व में एसईसीएल कुसमुंडा, गेवरा, दीपका, कोरबा के भू विस्थापितों के लंबित रोजगार, बसावट एवं प्रभावित गांव की मूलभुत समस्याओं को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है गेवरा और कुसमुंडा में महाघेराव के बाद हेड क्वार्टर बिलासपुर के अधिकारियों के साथ चर्चा का आश्वाशन एसईसीएल प्रबंधन ने दिया था।

गेवरा कांफ्रेंस हाल में भू-विस्थापितों के समस्याओं को लेकर बैठक हुई जिसमें बिलासपुर से पी एंडआईआर महाप्रबंधक अनूप कुमार संतोषी,एल एंड आर महाप्रबंधक शरद तिवारी, मेन पवार जीएम शशि किरण गेवरा,दीपका,कुसमुंडा,कोरबा के जीएमएके साथ अन्य अधिकारी और किसान सभा प्रतिनिधि मंडल की ओर से माकपा जिला सचिव प्रशांत झा,किसान सभा के नेता जवाहर सिंह कंवर,दीपक साहू, जय कौशिक, भू-विस्थापित संघ से रेशम,दामोदर,रघुए,शिवदयाल,वीर सिंह, सुभद्रा कंवर, बहतरिन बाई, बसंत चौहान, पवन, उमेश, बृजमोहन,मोहन यादव, समेत बड़ी संख्या में भू-विस्थापित उपस्थित थे।

बैठक में माकपा जिला सचिव प्रशांत झा,किसान सभा के नेता जवाहर सिंह कंवर,दीपक साहू, ने एसईसीएल के सभी क्षेत्रों के भू विस्थापितों के लंबित रोजगार,बसावट एवं प्रभावित गांव की मूलभुत समस्याओं की ओर अधिकारियों का ध्यानाकर्षण कराते हुए समस्याओं के निराकरण की मांग की जिस पर बिलासपुर के अधिकारियों ने रोजगार समेत सभी मांगों पर जल्द निराकरण के साथ अर्जन के बाद जन्म वाले रोजगार प्रकरणों को जल्द बोर्ड में रखने की बात सभी अधिकारियों ने कहा जिसपर माकपा जिला सचिव प्रशांत झा ने अधिकारियों से कहा कि आश्वाशन पर भरोसा नहीं है एसईसीएल को कार्य धरातल पर करते हुए कार्यों का रिजल्ट दिखाना होगा हर बार आंदोलन के बाद झूठा आश्वाशन प्रबंधन देता है जब तक निर्णायक निर्णय भू विस्थापितों के पक्ष में नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा बैठक 4 घंटे चली भू विस्थापितों को प्रबंधन की बातों पर भरोसा नहीं है इसलिए किसान सभा ने बिलासपुर के अधिकारियों को सीएमडी के नाम ज्ञापन सौंप कर मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी बिलासपुर से आए अधिकारियों को दी है।

किसान सभा ने प्रमुख मांग की है की वन टाइम सेटलमेंट कर रोजगार के पुराने लंबित मामलो का जल्द से जल्द निराकरण किया जाये और अर्जन के बाद जन्म वाले प्रकरण का निराकरण कर जिनकी भी जमीन अधिग्रहण की गई है उन्हे बिना शर्त रोजगार प्रदान किया जाए। खदान बंद हो जाने अथवा अनुपयोगी होने पर पुराने अर्जित भूमि को मूल खातेदारों को वापसी करायी जाये द्य कोरबा एवं कुसमुंडा क्षेत्र में अर्जित जमीन मूल खातेदारों को वापस किया जाए और जरूरत होने पर पुनरू अर्जन की प्रक्रिया पूरा कर पुनर्वास नीति के अनुसार भू विस्थापितों को लाभ दिलाया जाए। अर्जित गाँव से विस्थापन से पूर्व उनके पुनर्वास स्थल की सर्वसुविधायुक्त व्यवस्था किया जाये। आउट सोर्सिंग कार्यों में भू विस्थापितों एवं प्रभावित गांव के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। महिलाओं को स्व रोजगार योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जाए। पुनर्वास गांव में काबिज भू-विस्थापितों को पूर्ण काबिज भूमि का पट्टा दिया जाए। विजयनगर, नेहरु नगर,गंगानगर समेत सभी पुनर्वास गांव को पूर्ण विकसित माडल गांव बनाने समेत 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। एसईसीएल के आश्वाशन से थके भू विस्थापितों ने अब आर पार लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है किसान सभा ने एलान करते हुए कहा है कि 10 दिनों में भू-विस्थापितों के समस्याओं पर सकारात्मक पहल कदमी होते नहीं दिखा तो 11 अगस्त को कुसमुंडा और 17 अगस्त को गेवरा खदान बंद और कार्यालयों का घेराव किया जाएगा।

नगरनार स्टील प्लांट में उत्पादन का शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री के बस्तर आने की संभावना

- सीएमडी ने ब्लास्ट फर्नेस में कोक की चार्जिंग से पहले किया हवन-पूजन

जगदलपुर। नगरनार स्टील प्लांट में उत्पादन शुरू होने का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है, प्लांट प्रबंधन छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के पहले हर हाल में कमीशनिंग करने की तैयारी में है। इसके बाद प्लांट में उत्पादन का रास्ता साफ हो जायेगा। एनएमडीसी लिमिटेड के वित्त निदेशक और कार्यवाहक सीएमडी अलमिताभ मुखर्जी ने ब्लास्ट फर्नेस में कोक की चार्जिंग की प्रक्रिया सफलता पूर्वक शुरू की। इस अवसर पर आयोजित पूजा में भाग लेने के बाद श्री मुखर्जी ब्लास्ट फर्नेस के कंट्रोल रूम के लिए रवाना हुए जहां से उन्होंने इस प्रक्रिया को सफलता पूर्वक प्रारम्भ किया। मिली जानकारी के अनुसार नगरनार स्टील प्लांट केंद्र सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है, और स्टील प्लांट के कमीशनिंग में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आने की प्रबल संभावना है। इसी वर्ष छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होना है और अगले वर्ष लोकसभा चुनाव भी है इसलिए प्रधानमंत्री के बस्तर आने से इंकार नहीं किया जा सकता। प्लांट की कमीशनिंग में प्रधानमंत्री के बस्तर संभाग मुख्यालय में एक बड़ी सभा आयोजित होने की संभावना है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार नगरनार स्टील प्लांट एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है, इसकी अलग-अलग इकाइयों में सही समन्वय बनना अतिमहत्वपूर्ण है। आज की प्रक्रिया समन्वित संबंधों की श्रृंखला में से एक है, जो जल्द ही ब्लास्ट फर्नेस के चालू होने में परिणत होगी। ब्लास्ट फर्नेस द्वारा उत्पादित गर्म धातु को स्टील मेल्टिंग शॉप में स्टील में परिवर्तित किया जाएगा जिसे कन्टीन्यूस कास्टिंग मशीन के माध्यम से थिन स्लैब कास्टर और हॉट स्ट्रिप मिल में ले जाया जाएगा जहां एचआर कॉइल अंतिम उत्पाद के रूप में उभरेगा। इस दौरान श्री विनय कुमार, निदेशक तकनीकी, एनएमडीसी, श्री संजय कुमार वर्मा, निदेशक वाणिज्यिक और निदेशक तकनीकी, अतिरिक्त प्रभार (मेकॉन), श्री प्रवीण कुमार, कार्यकारी निदेशक और परियोजना प्रभारी नगरनार स्टील प्लांट, वरिष्ठ अधिकारी और श्रमिक संघों के प्रतिनिधि समारोह में उपस्थित थे।

सेवा सुशासन से अभिभूत संवाद है मोदी की मन की बात: रंजना

- मोदी की मन की बात सुनना राष्ट्र निर्माण का साक्षी बनाना है : रितेश

धमतरी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की मोदी की मन की बात के 103 में संस्करण में विधायक रंजना डीपेंद्र साहू ने भाजपा वरिष्ठजनों के साथ गंगरेल मंडल के ग्राम श्यामतराई में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बुथ क्रमांक 224 में अनेक कार्यकर्ताओं के साथ सुनी। जहां यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मन के बात के माध्यम से समस्त देशवासियों को श्रावण मास की शुभकामनाएं देते हुए कहां कि योग सिर्फ भारत देश ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध है, प्रकृति को पुनः स्थापित करने छोटे-छोटे प्रयास से वृक्षारोपण के माध्यम से करनें की बात कही है।

भारत की कलाकृतियां, संस्कृति और समृद्ध विरासत भारत की पहचान है, जो अनेक देश में हमारे भारत की पहचान बढ़ा रही है, देवभूमि और धर्म पर

मोदी जी ने भोजपत्र की प्राचीन विरासत और देश के आखिरी छोर माना जाने वाला गांव को प्रथम गांव माना जाना उपलब्धि बताया, उत्तर भारत सहित समस्त क्षेत्र में नशा पान को दूर करने के खिलाफ युवाओं का योगदान कि सराहना करते हुए, मेरी माटी मेरा देश अभियान तहत देश को बलिदानियों की कलाकृतियों से सुसज्जित करने और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा फ्हराने के आवाहन किए। मन की बात सुनकर विधायक रंजना डीपेंद्र साहू ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन से अभिभूत महत्वकांक्षी संवाद है मोदी जी की मन की बात, किसान हितैषी मोदी सरकार जिन्होंने किसान सम्मान निधि का वितरण दिवस पर कोटेड यूरिया का शुभारंभ कर किसानों को संप्रेषित किए जो धान के लिए सर्व उपयोगी होगा, अच्छी कृषि पद्धति की जानकारी मिल सके उसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में किसान समृद्धि केंद्र का शुभारंभ किया जिससे विभिन्न सरकारी योजनाओं और खुदरा विक्रय की जानकारी किसानों को मिल सके। विधायक श्रीमती साहू ने आगे कहा कि मन की बात कार्यक्रम सभी को एक साथ ला रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण कर मन की बात के माध्यम से जनभागीदारी की बड़ी ताकत देश में दिखाई दे रही है। पार्षद रितेश नेताम ने कहा कि मोदी जी की मन की बात का सुनना राष्ट्र निर्माण में साक्षी बनना है, क्योंकि नित प्रति दिन यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक योजनाएं देश हित के लिए लाई जा रही है और नए भारत का निर्माण किया जा रहा है।

एनएसयूआई का प्रदर्शन, परीक्षा में सभी विद्यार्थियों को मिले एक समान नंबर

गौरेला पेंड्रा मरवाही। डॉ. भंवर सिंह पोर्ते शासकीय महाविद्यालय में सोमवार को एनएसयूआई छात्र संगठन ने प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने विश्व विद्यालय प्रबंधक पर हिंदी अंग्रेजी जैसे विषयो में छात्र-छात्राओं को एक या दो नंबर के लिए पूरक में डालने का आरोप लगाया है। एनएसयूआई ने मामले में जांच और दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही नवीन कन्या महाविद्यालय को पेंड्रा में खोले जाने की भी मांग की है, जिसे गौरेला में खोलने की तैयारी की जा रही है। वहीं, जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष ने प्राचार्य के कार्य प्रणाली पर सवाल जरूर उठाया है।

एनएसयूआई का आरोप है कि महाविद्यालय में मुख्य परीक्षा सत्र 2022-23 में कुछ विषयों का परीक्षा परिणाम सही नहीं आया है। छात्रों के अनुसार, बीकॉम, बीए और बीएससी के कुछ विषय शामिल हैं, जिसमें मुख्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी है। मूल्यांकनकर्ता द्वारा एक विषय में अधिकांश छात्रों को एक समान अंक दिए गए हैं। इससे छात्रों का परीक्षा परिणाम खराब हो गया है और छात्र फेल हो गए। कुछ छात्र पूरक हो गए, जबकि छात्रों का संबंधित विषय का पेपर अच्छा बना था। अधिकांश छात्रों को एक समान अंक देना से संगत ही नहीं है, इसमें साफ समझ आ रहा है कि मूल्यांकनकर्ता की गलती की वजह से ऐसा हुआ है।

वहीं, छात्रों ने पेंड्रा में इस सत्र में खोले जाने वाले नवीन कन्या महाविद्यालय जो पेंड्रा के नाम से आया था, उसे योजनाबद्ध तरीके से बिना जनभागीदारी समिति की जानकारी दिए बेगैर गौरेला में खोले जाने का भी विरोध किया है। इस मामले में जनभागीदारी समिति अध्यक्ष सहित छात्रों ने भी प्राचार्य के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा किया है। भंवर सिंह पोर्ते शासकीय महाविद्यालय पेंड्रा की प्राचार्य ने कहा कि नवीन कन्या महाविद्यालय पेंड्रा में खोले जाने की कार्रवाई जारी है। हालांकि उन्होंने कैमरे में इस मामले में कुछ भी नहीं कहा।

भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने अमोदा शक्ति केन्द्र में किया वरिष्ठजनों का सम्मान

जांजगीर। भाजपा जिला उपाध्यक्ष अमर सुल्तानिया के द्वारा ग्राम अमोदा के सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल प्रांगण में शक्ति केन्द्र अमोदा के ग्राम भादा, भैसदा, अमोदा, नवापारा के वरिष्ठजन बुजुर्गो का सम्मान कार्यक्रम आयोजन किया गया एवं सभी के साथ भोजन का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष अमर सुल्तानिया ने कहा कि ऐसे कार्यकर्ता जो लगातार बूथ स्तर पर पार्टी के लिए सतत् समर्पित होकर कार्य करते है, जिन्होने अपने जीवन काल में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा सीटों पर 2 सीट से 300 सीट तक ले जाने का काम किया है, छत्तीसगढ़ में लगातार 3 बार भाजपा सरकार बनाने वाले पूज्यनीय कार्यकर्ता जिनकी मेहनत तपस्या से आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जानी जाती है, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं के साथ भोजन का कार्यक्रम रखा गया हैं, साथ ही जो बहुत वरिष्ठ हो चुके है ऐसे वरिष्ठजनों को साल व श्रीफ्ल से सम्मानित किया गया। ऐसे लोग जो विभिन्न क्षेत्रो में गांव के विकास के लिए काम किया उनका सम्मान किया गया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष अमर सुल्तानिया जी द्वारा अमोदा शक्ति केन्द्र के ग्राम भादा, भैसदा, अमोदा, नवापारा ग्राम के बाबूलाल लहमोर, विशाल यादव, श्रीमती सरिता

देवांगन, दलेश्वर यादव, फेकूलाल यादव, विश्वनाथ सिंह, गोविंद केंवट, रेशमलाल साहू, का सम्मान साल व श्रीफ्ल भेंटकर किया एवं उनके साथ समय बिताकर उनके साथ भोजन किया एवं उनके अनुभव को साक्षा किया।

इस अवसर पर कार्यक्रम में भाजपा जिला उपाध्यक्ष अमर सुल्तानिया, हितेश यादव, जितेन्द्र खाण्डे, मुकेश भोपालपुरिया, सुनील पाण्डे, रामलल्ला सिंह, भागीरथी धीवर, साहेबलाल साहू, कुशल देवांगन, गंगाराम नामदेव, विनोद सिंह, विश्वनाथ सिंह, कौशिक साहू, सीताराम यादव, वेदप्रकाश धीवर, जीवनलाल नामदेव, दीपक नामदेव, सीताराम साहू, ननकू, शरद कुमार, भोगसिंह, सोनू साहू, रामेश्वर केंवट, श्यामलाल यादव, तेरस, संतोष यादव, गोविंद श्रीवास, छोटू यादव, रामशंकर यादव, गोंविद केंवट, डुलेश्वर साहू, बोधराम पटेल, देवनारायण, हरिचरण, बसंत, सीताराम बरेठ आदि उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

पेगड़ापल्ली व तारलागुडा पोटाकेबिन के 140 बच्चे आई फ्लू से हुए संक्रमित

बीजापुर। भोपालपटनम में आई फ्लू का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, दो पोटाकेबिन के 140 बच्चे आई फ्लू से संक्रमित हो गए हैं, सभी बच्चों का इलाज चल रहा है। भोपालपटनम बीएमओ चेलपत राव ने बताया कि पेगड़ापल्ली बालक पोटाकेबिन में पानी भर गया था, सभी बच्चे को सांन्ड्रापल्ली बालक आश्रम में भेजा गया था, बालक आश्रम के 110 बच्चों में आई फ्लू के लक्ष्ण के बाद उन्हें दवाई दी जा रही है। स्थिति नियंत्रण में हैं, तारलागुडा कन्या पोटाकेबिन की अधिक्षिका समेत करीब 30 छात्राओं में आई फ्लू संक्रमण के बाद उनका इलाज किया जा रहा है। आई फ्लू का संक्रमण के फलाव को देखते हुए एहतियात के तौर पर कन्या पोटाकेबिन संगमपल्ली में 300 व बालक आश्रम में 100 बच्चों का स्वास्थ्य जांच किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम फिलहाल सभी आश्रम और पोटाकेबिन में दौरा कर रही आई फ्लू की जांच कर रही है।

छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खिलाड़ियों को कैरियर बढ़ाने का एक सुनहरा मौका

धमतरी। छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष मोहन लालवानी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का छत्तीसगढिया ओलंपिक खेल को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में स्थानीय और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना है। जिससे राज्य में छिपी खेल प्रतिभा का उजागर हो सके। ग्राम लोहरसी में राजीव युवा मितान क्लब के तत्वावधान में आयोजित जोन स्तरीय छत्तीसगढिया ओलंपिक प्रतियोगिता के समापन समारोह में कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री लालवानी ने कहा कि यह खुशी की बात है कि ओलंपिक खेल में शहरी और ग्रामीण ईलाकों के सभी आयुवर्ग के नागरिक हिस्सा ले रहे हैं। यह खेल आयोजन राज्य में छिपी हुई खेल प्रतिभा को खेल के मैदान तक लाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। जिसके माध्यम से राज्य के प्रतिभाशाली खिलाडियों की पहचान हो सकेगी और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिये तैयार किया जा सकेगा।

विशाल निःशुल्क आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक नेत्र रोग एवं पंचकर्म चिकित्सा शिविर संपन्न

दल्लीराजहरा। निःशुल्क आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक नेत्र रोग एवं पंचकर्म चिकित्सा शिविर में 387 मरीजों ने लाभ लिया। शिविर में 12 मरीजों के आँखों की जांच की गयी। संचालक आयुष छत्तीसगढ़ शासन रायपुर एवं जिला आयुर्वेद अधिकारी बालोद के मार्गदर्शन में 30 जुलाई को स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कमलचंद जैन के पुण्य स्मृति में समरथ जैन भवन में किया गया। शिविर के मुख्य अतिथि शीबू नायर अध्यक्ष नगर पालिका परिषद दल्ली राजहरा एवं विशेष अतिथि गोविंद वाधवानी अध्यक्ष राजहरा व्यापारी संघ थे। शिवि का शुभारम्भ् धन्वंतरि भगवान की पूजा अर्चना के पश्चात किया गया । इस शिविर में डॉ नरेंद्र कुमार ठाकुर ,डॉ आशुतोष पाठक, डॉ कामना पाठक ,डॉ पूर्णिमा राजपूत, डॉ अशोक वर्मा, डॉ शिवकुमार बारले, डॉ सत्येंद्र वर्मा,फार्मासिस्ट रामसेवक परसाई, अरुण देशमुख, विमल देवांगन, सबिहा अल्वी, शीतल चौहान ,त्रिवेणी साहू, राधिका नेताम, आजाद साहू, आदि ने अपनी सेवाएं दी।

संगीत के महासंग्राम में पूर्वा बनी सुर सम्राट सुर सरगम का राज्य स्तरीय गायन स्पर्धा

राजनांदगांव। संस्कारधानी राजनांदगांव की सांस्कृतिक संस्था सुर सरगम द्वारा स्थानीय पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय गायन प्रतियोगिता सुर सम्राट का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में पूर्व सांसद मधुसूदन यादव, कुलबीर छाबड़ा, निखिल द्विवेदी और नीलू शर्मा उपस्थित थे। प्रतियोगिता में सुर सम्राट का खिताब पूर्वा श्रीवास्तव ने हासिल किया। कार्यक्रम के संयोजक वरिष्ठ रंगकर्मी शरद श्रीवास्तव ने बताया कि राजनांदगांव जिले सहित प्रदेश के संगीत से जुड़े कलाकारों को मंच प्रदान करने सुर सरगम संस्था ने राज्य स्तरीय गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न जिलों से कुल 58 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पूर्वा श्रीवास्तव, द्वितीय वैष्णवी रंगारी और तृतीय स्थान अतीक अहमद ने प्राप्त किया, जिन्हें क्रमशः सात हजार, पांच हजार व तीन हजार रूपये सहित स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।

बाघ दिवस के अवसर पर बाघों के संरक्षण से संबंधित लघु नाटिका आयोजित

कोरबा। भारत में बाघों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। बढ़ते शहरीकरण और सिमटते जंगलों ने बाघों से उनका आशियाना छीन लिया है। मानव ने भी बाघो के साथ क्रूरता बरतने में कोई कसर नही छोड़ी है । बाघ पारिस्थितिक पिरामिड तथा आहार श्रृंखला में सबसे बड़ा उपभोक्ता है। बात हाईस्कूल स्याहीमुड़ी की प्राचार्य फरहाना अली ने स्कूल परिसर मे भुंइया इको क्लब के तत्वावधान में आयोजित बाघ दिवस के अवसर पर कही। उन्होने कहा कि विश्व वन्यजीव कोष के अनुसार पूरे विश्व मे लगभग चार हजार बाघ बचे हैं, जिनमे सबसे ज्यादा तीन हजार छह सौ बाघ भारत मे हैं। इको क्लब प्रभारी प्रभा साव एवं पुष्पा बघेल की उपस्थिति में बाघ दिवस के अवसर पर बाघों के संरक्षण से संबंधित स्लोगन एवं लघु नाटिका प्रस्तुत की गई। छात्रों द्वारा बाघ का मुखौटा एवं बाघ का ड्रेस पहनकर बाघों के साथ हो रही बर्बरता को दिखाने का प्रयास किया गया।

फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 2 अगस्त को

कांकेर। विधानसभा निर्वाचन-2023 की तैयारी के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का द्वितीय विशेष पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01 अक्टूबर 2023 की स्थिति में जिले के तीनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमशः 79 अंतागढ़(अजजा), 80-भानुप्रतापपुर एवं 81-कांकेर (अजजा) अंतर्गत प्रारंभिक प्रकाशन 02 अगस्त 2023 को किया जावेगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार 02 अगस्त को प्रारंभिक प्रकाशन किये गये मतदाता सूची का जिले के सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम सभा में वाचन किया जावेगा। आयोग के मंशानुरूप ग्राम सभाओं में निर्वाचक नामावलियों का वाचन से निर्वाचक नामावली को शत-प्रतिशत शुद्धिकरण,

मताधिकार हेतु कोई मतदाता न छूटे एवं अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया जा सकेगा। आम नागरिक 02 अगस्त को प्रारंभिक प्रकाशन के दौरान निर्वाचक नामावली का अवलोकन बूथ लेवल अधिकारियों एवं अभिहित अधिकारियों तथा संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में कर सकते हैं। प्रारंभिक प्रकाशन 02 अगस्त से 31 अगस्त तक दावा आपत्ति स्वीकार किये जायेंगे। इस दौरान 12 अगस्त शनिवार एवं 13 अगस्त रविवार, 19 अगस्त शनिवार एवं 20 अगस्त रविवार को विशेष शिविर का भी आयोजन किया जावेगा। विशेष शिविर के दौरान दावा आपत्ति एवं फॉर्म 06, 07, 08 एकत्र किये जायेंगे। दावा-आपत्ति उपरांत 04 अक्टूबर को निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा।

प्रारंभिक प्रकाशन के संबंध में आज बैठक

अर्हता तिथि 1 अक्टूबर 2023 के संदर्भ में एकीकृत मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 02 को जिले के तीनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत सभी मतदान केंद्रों में किया जावेगा। उक्त संबंध में आवश्यक चर्चा हेतु 01 अगस्त को सायं 04 बजे जिला कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई है। आयोग के निर्देशानुसार प्रेस एवं मीडिया की उपस्थिति में फोटोयुक्त मतदाता सूची की हार्ड कॉपी एवं फोटो रहित सॉफ्ट कॉपी प्रदाय की जावेगी।

सीआरपीएफ जवान के लिए बनाया गया ग्रीन कोरिडोर, गंभीर हालत में दिल्ली किया जा रहा रेफर

जगदलपुर। बीजापुर के 153 सीआरपीएफ बटालियन में तैनात जवान को सेब्रीरियल मलेरिया के चलते मेकाज में भर्ती किया गया, जहां उसकी खराब हालत को देखते हुए जवान को दिल्ली रेफर किया जा रहा है। जवान की खराब हालत को देखते हुए शहर में ग्रीन कोरिडोर बनाया गया है।

बताया जा रहा है कि असम निवासी एकन राय 25 वर्ष की अचानक से स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसे बीजापुर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे बेहतर उपचार के लिए मेकाज में 28 जुलाई को भर्ती किया गया। जहां लगातार उसके स्वास्थ्य में सुधार नहीं दिखने के कारण आला अधिकारियों ने उसे दिल्ली रेफर करने की बात कही, जिसके चलते रविवार को एक प्लेन दिल्ली से बुलवाया भी गया था, लेकिन दिल्ली से प्लेन रविवार को निकल ही नहीं पाया। जिसके चलते सोमवार को प्लेन दिल्ली एसएस निकलकर हैदराबाद पहुंचा, जहां सुबह 11 बजे हैदराबाद से प्लेन जगदलपुर के लिए निकलने की बात कही गई। आला अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही प्लेन जगदलपुर के एयरपोर्ट में उतरता है, तत्काल ही टीम के द्वारा जवान को पूरी सुविधाओ से लैस एंबुलेंस में लेकर एयरपोर्ट के लिए रवाना किया जाएगा। जहां इस जवान को ले जाने के दौरान किसी भी प्रकार से कोई बाधा ना हो इसके लिए ग्रीन कोरिडोर तैयार करने के साथ ही थाना से लेकर यातायात की टीम को तैनात कर दिया गया है। जिससे की जवान को ले जाने के दौरान किसी भी तरह से कोई बाधा ना हो सके, वहीं बताया जा रहा है कि जवान वर्ष 2021 से बीजापुर में तैनात है, वह असम का रहने वाला है, साथ ही जवान विवाहित बताया जा रहा है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

मोदी को आज लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित करेंगे पवार

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शरद पवार होंगे, जो पीएम को सम्मानित करेंगे। इस दौरान पीएम दगडूशेठ गणपति मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएमओ ने बयान में कहा, पुणे मेट्रो फेज-1 के दो गलियारों के उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार दोपहर 12.45 बजे मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये खंड फुगेवाड़ी स्टेशन से सिविल कोर्ट स्टेशन और गरवारे कॉलेज स्टेशन से रूबी हॉल क्लिनिक स्टेशन तक हैं। इस परियोजना की आधारशिला भी पीएम मोदी ने 2016 में रखी थी। कार्यक्रम में पीएम मोदी और शरद पवार के एक मंच पर होने से सियासित तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन के कुछ सदस्यों ने इस पर एतराज जताया है।

एमवीए ठान लें तो महाराष्ट्र में बदलाव ला सकता है: पवार

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) मजबूत निर्णय लें, तो वे महाराष्ट्र में बदलाव ला सकते हैं। आपको बता दें कि शरद पवार की राकांपा, कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) राज्य में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के घटक हैं। पवार ने यह भी दावा किया कि वर्तमान राज्य सरकार के साथ जुड़ना मुश्किल है। शरद पवार का यह बयान ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर तीनों दल अलग-अलग बातें कर रहे हैं। पवार ने याद किया कि कैसे पिछली सरकारों ने प्राचीन कला और संस्कृति, साहित्य और इतिहास को संरक्षित करने में मदद की। उन्होंने कहा, ''लेकिन अब हमारे लिए मौजूदा सरकार के साथ काम करना मुश्किल है, परंतु कोई समाधान निकलना चाहिए। अगर हम तीनों (एमवीए के घटक) फैसला कर लें तो बदलाव हो सकता है।''

कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया

नईदिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी के इलाज और अन्य घरेलू खर्चों के लिए बैंक खाते से कुछ रकम निकालने की अनुमति मांगी थी। इस अकाउंट को ईडी ने सीज कर दिया है। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। कोर्ट इस अर्जी पर 4 अगस्त को सुनवाई करेगी। सिसौदिया ने रकम निकालने की इजाजत मांगी है क्योंकि बैंक कोर्ट के लिखित आदेश के बिना रकम निकालने की इजाजत नहीं दे रहा है। सिसोदिया की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद इरशाद ने कहा कि बैंक उन्हें चिकित्सा और अन्य खर्चों के लिए आवश्यक राशि निकालने की अनुमति नहीं दे रहा है। इस बीच, अदालत ने सीबीआई को शेष आरोपियों को दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अदालत को सूचित किया गया कि कुछ आरोपी व्यक्तियों को दस्तावेज़ पहले ही उपलब्ध करा दिए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिवकुमार को दी राहत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भ्रष्टाचार मामले में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को राहत दी है। दरअसल, उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार के एक मामले में उनके खिलाफ सीबीआई की जांच पर अंतरिम रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने मामले में हाईकोर्ट के 10 फरवरी के आदेश के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सीबीआई के पक्ष में आदेश होने के बावजूद जांच पर अंतरिम रोक लगाने की मंजूरी दे दी थी। वहीं, शिवकुमार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की है, लेकिन हाईकोर्ट की खंडपीठ के बाद में दिए अंतरिम आदेशों को चुनौती देने से इनकार कर दिया है।

शिवसेना विधायक ने प्रियंका पर की विवादित टिप्पणी

मुंबई। शिवसेना विधायक संजय शिरसाट ने राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी पर विवादित टिप्पणी की, जिसे लेकर उनकी तीखी आलोचना हो रही है। बता दें कि प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना (उद्धव) पार्टी से सांसद हैं। संजय शिरसाट की टिप्पणी पर प्रियंका चतुर्वेदी ने भी पलटवार किया है और संजय शिरसाट को गद्दार बता दिया है। वहीं आदित्य ठाकरे ने भी संजय शिरसाट की टिप्पणी की आलोचना की है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के विधायक संजय शिरसाट ने दावा किया है कि आदित्य ठाकरे ने प्रियंका चतुर्वेदी को उनकी सुंदरता की वजह से राज्यसभा भेजा है। संजय शिरसाट ने दावा किया है कि यह बात उन्हें पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे ने बताई थी। चंद्रकांत खैरे उद्धव ठाकरे की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। संजय शिरसाट की टिप्पणी पर प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं कैसी दिखती हूं और मैं आज जहां हूं, वहां कैसे पहुंची हूं, ये बताने के लिए मुझे किसी गद्दार की जरूरत नहीं है।

लोकसभा में सिनेमैटोग्राफी संशोधन बिल पास

गतिरोध बरकरार, दोनों सदन स्थगित

नईदिल्ली। संसद के मानसून सत्र में विपक्षी दल और सत्ता पक्ष के बीच वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। दोनों सदनों में गतिरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी विपक्षी दलों के शोर-शराबे के कारण संसद के कार्यवाही नहीं हो सकी। विपक्ष मणिपुर पर साफ तौर पर चर्चा की मांग कर रहा है। सरकार भी कह रही है कि हम चर्चा को तैयार हैं। बावजूद इसके संसद में हंगामा लगातार जारी है। विपक्ष का दावा है कि उनके नेताओं को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्षी दल चर्चा से भाग रहे हैं, उनकी दाढ़ी में कुछ काला है। मणिपुर मुद्दे पर राज्यसभा की बैठक चार बार बाधित होने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं, लोकसभा में भी गतिरोध बरकरार करने के कारण कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

लोकसभा की कार्यवाही

- लोकसभा में सोमवार को भी मणिपुर के मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों की तरह गतिरोध बरकरार रहा और विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न करीब 2ः50 बजे दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी।

- कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि सरकार लोकसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं करा रही है जो संसद का अपमान है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा कि सरकार को सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करानी चाहिए।

- संसद ने सोमवार को 'चलचित्र संशोधन विधेयक, 2023' को मंजूरी दे दी जिसमें फिल्मों का आयुवर्ग के हिसाब से वर्गीकरण करने और फिल्?म उद्योग में पायरे?सी को नियंत्रित करने संबंधी प्रावधान हैं। इस विधेयक में फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग एवं उसका प्रदर्शन करने पर दोषियों के खिलाफ जुर्माने एवं सजा का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा में मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीचविधेयक पर संक्षिप्त चर्चा हुई और इस पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी दे

दी।

- सरकार ने सोमवार को बताया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए दुनिया का सबसे ऊंचा ध्वज स्तंभ (पोल) इंफाल में स्थापित करने के लिए मणिपुर सरकार से प्रस्ताव मिला है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में महबूब अली कैसर के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

राज्यसभा की कार्यवाही

- राज्यसभा में सोमवार को मणिपुर के मुद्दे पर सूचीबद्ध अल्पकालिक चर्चा शुरू नहीं हो सकी क्योंकि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सदन में बयान की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा और नारेबाजी जारी रही जिसके कारण बैठक चार बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।

- सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में लगभग 44 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को अभी तक नल के पानी का कनेक्शन नहीं मिला है। जल शक्ति राज्य मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में सोमवार को कहा कि 2.17 करोड़ (55.3 प्रतिशत) ग्रामीण आदिवासी घरों में से 1.2 करोड़ के पास नल के पानी का कनेक्शन है।

- भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने संसद में विधायी एजेंडा को आगे बढ़ाने और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होने देने को लेकर सत्ता पक्ष की विपक्ष द्वारा की जा रही आलोचना को खारिज करते हुए सोमवार को कहा कि न तो नियम और न ही परिपाटी सत्तारूढ़ दल के लिए पहले बहुमत साबित करना अनिवार्य बनाती है। राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संवाददाताओं से कहा कि हर कोई जानता है कि सरकार के पास लोकसभा में दो तिहाई बहुमत है और संख्या बल इसके पक्ष में है।

- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 9.60 करोड़ कनेक्शन दिए गए हैं और ऐसे लाभार्थियों के बीच प्रति व्यक्ति औसत खपत 3 से बढ़कर 3.71 हो गई है। आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) कनेक्शन प्रदान करने की खातिर 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी।

मणिपुर मुद्दे पर सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रहा विपक्ष: निर्मला सीतारमण

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष मणिपुर मुद्दे पर चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहता। आज जब यह मुद्दा संसद में उठाया गया तो विपक्ष चर्चा से भागता नजर आया। विपक्ष के व्यवहार से दुखी हूं। उन्होंने कहा कि मणिपुर जैसे संवेदनशील मसला विपक्ष के लिए सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है। आज यह साबित हो गया कि वे मणिपुर मुद्दे पर सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे। अगर उन्हें वास्तव में परवाह होती, तो वे इस पर चर्चा करते। उन्होंने कहा कि आज आपने राज्यसभा में देखा कि आज सुबह सूची में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा होनी तय थी। जब चर्चा शुरू होने का समय आया, तो विपक्ष ने इससे किनारा कर लिया। यह तो पहले से तय था। सदन के नेता इसके लिए तैयार थे। विपक्षी नेता भी इसके लिए तैयार थे, लेकिन जब समय आया तो सभी ने बाहर जाना जरूरी समझा। वित्त मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि आइए चर्चा करिए। सरकार तैयार है। आपके नेता तो मणिपुर जाकर आएं हैं। वहां के लोगों से चर्चा कर के आए हैं। लोगों का दर्द साझा किया है। तो आइए चर्चा सदन में भी चर्चा करिए। सरकार इसके लिए पहले दिन से तैयार है। कोई भी रुकावट नहीं आएगी।

केंद्र सरकार ने कहा

सुप्रीम कोर्ट मणिपुर हिंसा की जांच की निगरानी करे तो आपत्ति नहीं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संघर्षग्रस्त मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए एक व्यापक तंत्र विकसित करने का आह्वान किया और पूछा कि मई से राज्य में ऐसी घटनाओं में कितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि अगर शीर्ष अदालत मणिपुर हिंसा की जांच की निगरानी करती है तो भारत संघ को कोई आपत्ति नहीं है।

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं, मणिपुर में हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। शुरुआत में, उन दो महिलाओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पेश हुए, जिन्हें 4 मई के वीडियो में मणिपुर में नग्न परेड कराते हुए देखा गया था, उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले में एक याचिका दायर की है। मामले में सुनवाई चल रही है। शीर्ष अदालत ने 20 जुलाई को कहा था कि वह संघर्षग्रस्त मणिपुर में दो महिलाओं को नग्न घुमाने के वीडियो से गहरा परेशान है, और कहा कि हिंसा को अंजाम देने के लिए महिलाओं को साधन के रूप में इस्तेमाल करना संवैधानिक लोकतंत्र में बिल्कुल अस्वीकार्य है। वीडियो पर संज्ञान लेते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और मणिपुर सरकार को तत्काल उपचारात्मक, पुनर्वास और निवारक कदम उठाने और की गई कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश दिया था।

27 जुलाई को, केंद्र ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि उसने संघर्षग्रस्त मणिपुर में दो महिलाओं को नग्न घुमाए जाने से संबंधित मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है, यह कहते हुए कि सरकार महिलाओं के खिलाफ किसी भी अपराध के प्रति शून्य सहिष्णुता रखती है।

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने अपने सचिव अजय कुमार भल्ला के माध्यम से दायर एक हलफनामे में शीर्ष अदालत से समयबद्ध तरीके से मुकदमे के समापन के लिए मामले को मणिपुर के बाहर स्थानांतरित करने का भी आग्रह किया। मामले में अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

3 मई को राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से कई लोग मारे गए हैं और कई सौ घायल हुए हैं, जब बहुसंख्यक मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किया गया था।

मणिपुर मुद्दे पर गोवा विधानसभा में हंगामा, सभी विपक्षी सदस्य दो दिन के लिए निलंबित

पणजी। गोवा विधानसभा में सोमवार को मणिपुर मुद्दे पर हंगामा हो गया। इस दौरान हंगामा करने के लिए सभी सात विपक्षी सदस्यों को दो दिन के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया। जिन नेताओं को विधानसभा की कार्यवाही से निलंबित किया गया है, उनमें विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ, कांग्रेस विधायक एलटोन डीकोस्टा, कार्लोस फेरेरा, आप विधायक वेंजी वीगास, क्रूज सिल्वा, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विजय सरदेसाई और गोवा रिवोल्यूशनरी पार्टी के विरेश बोरकर शामिल हैं। गोवा विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद यूरी अलेमाओ ने सदन में मणिपुर हिंसा के मामले पर चर्चा की मांग की। अलेमाओ ने कहा कि शुक्रवार को क्रूज सिल्वा ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए प्राइवेट मेंबर प्रस्ताव दिया था लेकिन सभापति रमेश तावड़कर ने उसे अस्वीकार कर दिया। इसके विरोध में सोमवार को सभी विपक्षी सदस्य काले कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत-वेस्टइंडीज के बीच निर्णायक भिड़ंत आज

त्रिनिदाद। भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला मंगलवार (1 अगस्त) को त्रिनिदाद में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। दोनों ही टीमें फिलहाल सीरीज में 1-1 बराबरी पर हैं। पहले मैच में शानदार जीत हासिल करने वाली टीम इंडिया को दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज के हाथों 6 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी। अब दोनों ही टीमें तीसरे वनडे में जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। ऐसे में यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है।

भारत को उम्मीद है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे और निर्णायक वनडे मैच में मध्यक्रम में संजू सैमसन और सूर्यकुमार यादव को आजमाने का उसका प्रयोग सफल साबित होगा। वेस्टइंडीज से 2006 के बाद से एक भी वनडे सीरीज नहीं हारी भारतीय टीम ने बारबडोस में दूसरे वनडे में हार का सामना किया जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली को आराम दिया गया था। 6 विकेट से मिली हार के बाद कोच राहुल द्रविड़ ने कहा था कि भारतीय टीम अगले महीने होने वाले एशिया कप और फिर विश्व कप के मद्देनजर वृहत तस्वीर देख रही है, जिसमें देखना है कि अहम मुकाबलों में युवा खिलाड़ी कितना प्रभाव छोड़ पाते हैं। 50 ओवरों के प्रारूप में संघर्ष करते दिख रहे सूर्यकुमार लंबी पारी खेलकर मैच जिताने पर फोकस करेंगे। वहीं कई बार वापसी करने के बावजूद प्रभावित नहीं कर सके सैमसन के पास भी यह सुनहरा मौका है। वह दूसरे वनडे की ही तरह तीसरे नंबर पर उतर सकते हैं। सलामी बल्लेबाज ईशान किशन ने प्रभावित किया है, लेकिन शुभमन गिल अभी तक बड़ी पारी नहीं खेल पाये हैं। हार्दिक पंड्या ने पहले दो मैचों में गेंदबाजी की शुरूआत की लेकिन बल्ले से नाकाम रहे। पांच मैचों की टी20 सीरीज से पहले वह उपयोगी पारी खेलना चाहेंगे।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 367 अंक चढ़ा निफ्टी 19,750 के पार

नईदिल्ली। वैश्विक बाजारों से मिले पॉजिटिव रुझानों और इंट्रा-डे ट्रेड में शुरुआती गिरावट के बाद सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को घरेलू शेयर बाजार करीब 367 अंकों की छलांग के साथ हरे निशान पर बंद हुए। मेटल और आईटी शेयरों में तेजी के दम पर घरेलू बाजार सोमवार के इंट्रा-डे ट्रेड में आई शुरुआती गिरावट से उबर गए। आज के कारोबार में फ्रंटलाइन सूचकांक सेंसेक्स 367.47 अंक मजबूत हुआ। निफ्टी में भी 108 अंकों की बढ़त दर्ज की गई। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 367.47 अंक यानी 0.56 फीसदी की बढ़त के साथ 66,527.67 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 66,598.42 की ऊंचाई तक गया और नीचे में 65,998.90 तक आया। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी ने भी 107.75 अंक यानी 0.55 फीसदी की बढ़त दर्ज की। निफ्टी दिन के अंत में 19,753.80 अंक पर बंद हुआ।

फॉक्सकॉन 16 अरब रु. खर्च कर भारत में लगाएगी प्लांट

नईदिल्ली। ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन की एक यूनिट ने तमिलनाडु सरकार के साथ एक बड़े सौदे पर हस्ताक्षर किया है। कंपनी इस सौदे के तहत भारत के इस राज्य में राज्य में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट तैयार करने के लिए एक बड़ा प्लांट बनाएगी और इससे करीब 6,000 से ज्यादा नौकरियां मिलेगी। यह जानकारी रॉयटर्स ने राज्य सरकार के एक वरिष्ठ सूत्र ने दी। फॉक्सकॉन की सहायक कंपनी, फॉक्सकॉन इंडस्ट्रियल इंटरनेट ने राज्य की राजधानी चेन्नई के पास कांचीपुरम जिले में एक कैंपस बनाने के लिए 16 अरब रुपये (194.45 मिलियन डॉलर) का निवेश करने की योजना बनाई है। रॉयटर्स को यह जानकारी एक सूत्र के हवाले से मिली, जो यह जानकारी पब्लिक को देने के लिए अधिकृत नहीं था।

फ्लिपकार्ट का 77 फीसदी हिस्सेदारी वालमार्ट के नाम

नईदिल्ली। वालमार्ट इंक ने ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट में अपनी 5 फीसदी हिस्सेदारी और बढ़ा दी है। कंपनी ने आज फ्लिपकार्ट में टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट की शेष हिस्सेदारी भी खरीद ली है। ब्लूमबर्ग ने बताया कि यह डील 1.4 अरब डॉलर में हुई यानी टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट की फ्लिपकॉर्ट में हिस्सेदारी खरीदने के लिए वालमार्ट ने 1.4 अरब डॉलर की अदायगी की। ब्लूमबर्ग ने बताया कि ऐसे समय में जब नकदी को लेकर सख्ती बरकरार है, कंपनी की इस खरीदारी से भारतीय रिटेलर पर दांव बढ़ जाएगा और मनी मैनेजर को निवेशकों को डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करने में मदद मिलेगी। ब्लूमबर्ग न्यूज को मिले टाइगर ग्लोबल द्वारा निवेशकों को भेजे गए एक लेटर के अनुसार, हाल के दिनों में हुए ट्रांजैक्शन में भारतीय ई-कॉमर्स दिग्गज का मूल्य 35 अरब डॉलर आंका गया। यह फ्लिपकार्ट के 2021 के फंडिंग राउंड में हासिल किए गए लगभग 38 अरब डॉलर के मूल्यांकन से कम है।

इंडिया के सुपर प्रीमियम खंड में 50% बाजार हिस्सेदारी पर है सैमसंग की नजर

सियोल। दक्षिण कोरिया की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सैमसंग की भारत के सुपर प्रीमियम खंड में 50% बाजार हिस्सेदारी हासिल करने पर नजर है। कंपनी को उम्मीद है कि वह अपनी फोल्डेबल डिवाइस गैलेक्सी फोल्ड 5 और गैलेक्सी फ्लिप 5 के जरिए इस लक्ष्य को हासिल करने में सफल होगी। फिलहाल भारत के सुपर प्रीमियम स्मार्टफोन खंड में आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल का दबदबा है। इस श्रेणी में 1,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक कीमत वाले हैंडसेट शामिल हैं। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष और मोबाइल अनुभव कारोबार के प्रमुख टीएम रोह ने कहा कि कंपनी का लक्ष्य सुपर प्रीमियम खंड में गैलेक्सी फोल्ड 5 और गैलेक्सी फ्लिप 5 की पेशकश के साथ अपनी बाजार हिस्सेदारी को मौजूदा 35% से बढ़ाकर 50% करना है।

डिजिटल धोखाधड़ी से बचा पायेगा डेटा सुरक्षा का नया कानून?

स्वाति

आये दिन ऐसी खबरें आ रही हैं जब कहीं न कहीं कोई न कोई डिजिटल धोखाधड़ी का शिकार हो रहा है। बढ़ती आनलाइन ठगी और धोखाधड़ी को कारगर तरीके से रोकने के लिए केन्द्र सरकार संसद में एक महत्वपूर्ण विधेयक लेकर आयी है। हालांकि संसद के मौजूदा मानसून सत्र में हंगामों के बीच कई आवश्यक विधेयक अधर में लटके नज़र आ रहे हैं, इन्हीं विधेयकों में से वह %डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 भी है जो संसद में शोर की भेंट चढ़ता नज़र आ रहा है। 27 जुलाई को चर्चा के लिए लाया गया यह विधेयक विपक्ष के संसद से वॉक आउट की भेंट चढ़ गया। डिजिटल युग में इश्क की इबारतें भी सोशल मीडिया पर लिखी जा रही हैं। प्रेमी की तलाश में देश की सरहदों तक को लांघ दिया जा रहा है। लोन ऐप के ज़रिये लोन देकर परिवार को आत्महत्या तक के लिए विवश कर दिया जा रहा है। सेक्सटॉर्शन, गैस लाइटिंग, कैट फिशिंग जैसी घटनाएं मानसिक, आर्थिक, भावनात्मक और शारीरिक आघात पहुँचा रही हैं। ऐसे माहौल में इस विधेयक का पास होना कितना जरुरी है यह सरकार भी बखूबी समझ रही है।

पहली बार इस विधेयक को दिसंबर 2019 में पेश किया गया था, परंतु विभिन्न स्टेक होल्डर और एजेंसियों से सुझाव और आपत्तियां मिलने के बाद इसे वापस ले लिया गया था। सरकार ने पिछले नवंबर में नया मसौदा तैयार कर एक सार्वजनिक परामर्श शुरू किया था। जनता, 46 विभिन्न संगठनों और 38 सरकारी मंत्रालयों से प्राप्त सुझावों के आधार पर अब इसका खाका तैयार किया गया है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023, केंद्र द्वारा बनाए जा रहे

प्रौद्योगिकी नियमों के व्यापक ढांचे का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिसमें डिजिटल इंडिया विधेयक, भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 का मसौदा, और गैर-व्यक्तिगत डेटा प्रशासन के लिए एक नीति शामिल है। आगामी डिजिटल इंडिया बिल भारत के मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी अधिनियम) 2000 को प्रतिस्थापित करेगा। यह नया कानून भारत के डिजिटल परिदृश्य पर व्यापक निगरानी स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्रस्तावित विधेयक इंटरनेट प्लेटफ़ॉर्म, ऑनलाइन सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के नकारात्मक प्रभाव के बीच साइबर अपराध, डेटा सुरक्षा, डीपफेक, प्रतिस्पर्धा जैसी समकालीन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटता है। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के संगठन (यूएनसीटीएडी) के अनुसार, 194 देशों में से लगभग 137 देशों ने डेटा और गोपनीयता को सुरक्षित करने के लिए कानून बनाया है।

अफ्रीका और एशिया में क्रमशः 61% (54 में से 33 देश) और 57% (60 में से 34 देश) ने इसे अपनाया है। वही केवल 48% अल्प विकसित देशों (46 में से 22) के पास डेटा सुरक्षा और गोपनीयता कानून हैं। ऐसे कानूनों की जरूरत वैश्विक स्तर पर तो है ही मगर व्यक्तिगत रूप से बहुत से अवांछनीय स्थितियों से बचने के लिए भी है। बच्चों की साइबरबुलिंग, पहचान की चोरी, गैसलाइटिंग, डॉक्सिंग, प्रतिरूपण और कैटफ़िशिंग कुछ ऐसे ऑनलाइन अपराध हैं जिन्हें आगामी डिजिटल इंडिया बिल में दंडित किए जाने की संभावना है। डिजिटल नागरिक की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है परंतु स्वयं को किसी संकट से बचाने की जवाबदेही हर उस व्यक्ति की भी है हो विभिन्न तरह के ऐप को उपयोग में ला रहा। जिस लोन को मिलने की प्रक्रिया काफी जटिल है उसे कोई ऐप सरलता से देती है तो दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। किसी से चैट करते समय हमे अपने निजी विवरणों या फोटोग्राफ को शेयर करने से भी बचना चाहिए। बच्चे बेहिचक इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं लेकिन उन पर परिवार वालों की कड़ी निगरानी जरुरी है। किसी भी ऐप को कांटैक्ट लिस्ट, कैमरा, मेसेज आदि के लिए परमिशन देने से पहले अपनी डिजिटल सुरक्षा को भी दिमाग में रखना जरूरी होता है। प्रस्तावित विधेयक जब पारित होगा तो वह हमारे साथ धोखाधड़ी हो जाने पर कानूनी मदद जरूर देगा लेकिन धोखाधड़ी न हो इसके उपाय तो हमें ही करने होंगे।

विपक्ष के तरकश में आखिरी तीर

आदिति फडणीस

कई लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को कुछ ही दिनों में जिस अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा वह सेल्फ-गोल (आत्मघाती) जैसा ही है। लोकसभा में विपक्षी दल के एक सांसद का कहना है, 'हम अविश्वास प्रस्ताव को अपने तरकश का एक अहम हथियार मानते रहे हैं। लेकिन यह मुख्य मुद्दा नहीं था क्योंकि हमें इस बात का अच्छी तरह अंदाजा था कि आंकड़े हमारे खिलाफ हैं।' वह कहते हैं, 'अगर प्रधानमंत्री ने लोकसभा में 'मणिपुर' शब्द कहा होता (उन्होंने उस शर्मनाक वीडियो के बारे में संसद भवन के बाहर कुछ कहा और हमने सोचा कि वह सदन में भी इस मामले पर चर्चा करेंगे) तब हमने दबाव डाला होता कि इस पर चर्चा कराई जाए। हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री बोलें, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अब हमारे पास न केवल लोकसभा में बल्कि राज्यसभा में भी सरकार को कठघरे में खड़ा करने का मौका है और उनकी विफलता न केवल मणिपुर में साबित हुई है जबकि कई अन्य मुद्दों पर भी यह उजागर हुआ है और इसके लिए सरकार ही दोषी है।'

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी कहते हैं, 'यह संख्या बल का नहीं बल्कि नैतिकता का मामला है। कौन जानता है, मणिपुर में होने वाली घटनाएं शायद सत्ताधारी पार्टी के कुछ सांसदों को भी हमारे साथ मिलकर मतदान करने के लिए बाध्य कर दें!' विपक्ष सरकार पर निशाना साधने के लिए तैयार है। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन, संसद के मॉनसून सत्र में जितना संभव हो उतने विधेयकों को पारित करने के लिए आगे बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ असम के कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस तरह की कार्रवाई को 'अवैध' बताया है। गोगोई का कहना है, 'जब अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है और अध्यक्ष (ओम बिरला) ने इसे स्वीकार कर लिया है तब नियम यह है कि सरकार को अविश्वास प्रस्ताव को प्राथमिकता देनी चाहिए और अन्य सभी कार्यवाही रोक देनी चाहिए। सोच यह है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तब सरकार को इस्तीफा देना होगा और वैसी स्थिति में इसकी वैधता सवालों के घेरे में आ जाती है। यह सरकार विधेयकों को ऐसे पारित कर रही है जैसे यह कोई सामान्य दिनचर्या का काम हो। ' लोकसभा अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव के लिए उचित तारीख पर विचार कर रहे हैं और इसी दौरान खान एवं खनिज (विकास व विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023, राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक, 2023, और राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023 लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है। निचले सदन ने 30 मिनट में वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 पारित किया था। राज्यसभा में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022 ध्वनिमत से उस दौरान पारित किया गया जब विपक्ष ने वॉकआउट किया। राज्यसभा ने सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023 को भी मंजूरी दे दी। संसद भवन के बाहर केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, 'हमने विपक्ष से चर्चा (मणिपुर) कराने के लिए कहा था। लेकिन इनकी मांग अविश्वास प्रस्ताव को लेकर थी। निश्चित रूप से हम इस गुट को हरा देंगे लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्ष यह सोचता है कि सरकार इस बीच काम करना बंद कर देगी?' विशेषज्ञों का कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का मतलब सरकार के पास संख्याबल होना और आंकड़ों के आधार पर प्रस्ताव जीतना नहीं है बल्कि इसका संबंध पूरी राजनीति प्रक्रिया से है। उनका कहना है कि मौजूदा गतिरोध इसलिए पैदा हुआ कि प्रधानमंत्री ने संसद में मणिपुर पर बयान देने की विपक्ष की मांग नजरअंदाज कर दी। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव, प्रधानमंत्री को बोलने के लिए मजबूर कर सकता है कि वह मणिपुर पर बोलें या नहीं। संसदीय इतिहास के जानकार एक विशेषज्ञ का कहना है, 'अविश्वास प्रस्ताव में वाक्पटुता की पूरी आजमाइश होती है। अमूमन, इस दौरान गुणवत्तापूर्ण भाषण दिए जाते हैं। भारत के इतिहास में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान ही कुछ सर्वश्रेष्ठ संसदीय भाषण दिए गए हैं। अगर बोलने की बात आती है तब इस लिहाज से प्रधानमंत्री का भाषण शानदार होता है, वास्तव में विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं है जो उनकी बराबरी कर सके। हालांकि विपक्ष के पास राज्यसभा में अच्छे वक्ता हैं। लेकिन वहां इस मामले में नियम 267 के तहत चर्चा की जाएगी। यह समान नहीं होगा।' हालांकि इस बारे में कोई नियम नहीं है कि सरकार में किसे अविश्वास प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। सैद्धांतिक रूप से प्रधानमंत्री को ही प्रतिक्रिया देनी चाहिए।

सीधे आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी

शेखर गुप्ता

आगामी आम चुनाव के पहले दौर के मतदान में बमुश्किल आठ महीने का समय बचा है और चुनाव प्रचार अभियान जोर पकड़ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गतिविधियां, उनके भाषण, उनके सहायकों और तमाम प्रमुख राजनेताओं के भाषणों में इसे देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री के अहम विदेशी नीति संबंधी कदमों में भी इसे देखा जा सकता है। इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। प्रचार अभियान तो जल्दी शुरू हो ही गया है, साथ ही विपक्ष भी साझा उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। यह बात तो निर्वाचन वाले लोकतंत्रों के डीएनए में ही शामिल है कि विपक्ष हमेशा सत्ताधारी दल को पराजित करने का अवसर तलाश करता है। इस बार न केवल विपक्ष अधिक ऊर्जा के साथ चुनाव मैदान में है बल्कि गठजोड़ भी बुनियादी स्वरूप का है।

पिछले चुनाव में यानी 2019 में ऐसा नहीं था। कांग्रेस छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मिली जीत से उत्साहित थी। उसे यकीन था कि राहुल गांधी का 'चौकीदार चोर है' नारे पर आधारित प्रचार अभियान सटीक साबित होगा। इन हिंदी प्रदेशों में यह नारा कारगर रहा लेकिन देशव्यापी स्तर पर ऐसा नहीं हो सका। आपकी राजनीतिक स्थिति तय करेगी कि आप किस बात पर यकीन करते हैं। इस पर कि कांग्रेस भ्रमित थी और उसे उसकी जगह दिखा दी गई या फिर इस पर कि पुलवामा-बालाकोट ने पूरे चुनाव को इस तरह बदल दिया जैसा किसी ने सोचा भी नहीं था। जो भी हो, अंतिम नतीजे से तो हम वाकिफ ही हैं। पहला अंतर तो यह है कि इस बार बहुत जल्दी शुरुआत हो गई क्योंकि नजरें आम चुनाव पर हैं। इस हद तक कि तीन प्रमुख हिंदी प्रदेशों और तेलंगाना में कुछ माह पहले होने वाले चुनावों पर भी उतना ध्यान नहीं है। अतीत में राज्यों के चुनावों को दिशा दिखाने वाला माना जाता था। परंतु इस अवसर पर हमें छोटे से मगर साहसी राज्य मिजोरम को भी शामिल करना चाहिए जहां लोकसभा की केवल एक सीट है लेकिन यह मणिपुर का अहम पड़ोसी है और इसकी सरकार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सदस्य है और अधीर हो रही है। हालात कुछ ऐसे हैं मानो सबसे बड़ी राजनीतिक लीग में सेमीफाइनल हुए ही नहीं और सीधे फाइनल की शुरुआत हो गई। तीन बातों ने इन चुनावों को मोदी और भाजपा के लिए खासतौर पर चुनौतीपूर्ण बना दिया है

'इंडिया' के गठन के साथ ही देशव्यापी स्तर पर राजनीतिक दलों का एक साझा गठजोड़

तैयार हो चुका है। हालांकि उनके पास केवल 144 सांसद हैं लेकिन यह गठजोड़ 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक सीमित है। इसके अलावा इस गठजोड़ के सदस्य दल 11 राज्यों में सत्ता में हैं। इसके अतिरिक्त अतीत के तीसरे मोर्चे जैसी खिचड़ी के उलट इसके मूल में कांग्रेस के रूप में एक राष्ट्रीय पार्टी है। के. चंद्रशेखर राव के दल भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) जैसे दल अगर इससे जुड़ते हैं तो यह और मजबूत नजर आएगा।

भाजपा के दोबारा बहुमत हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़ भी दें तो अधिकांश हिंदी भाषी राज्यों में पार्टी का जीतना अहम है। पार्टी के पक्ष में जो कई कारक काम कर सकते हैं उनमें से एक है विपक्ष के वोटों का बंटवारा या फिर उन वोटों का बंटवारा जिनके भाजपा की ओर जाने की उम्मीद नहीं। खासतौर पर मुस्लिम मत। भाजपा के लिए यह जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी के दल एआईएमआईएम के बीच बंट जाएं। कर्नाटक ने संकेत दिया है कि मुस्लिम वोट अब ऐसे दल के खिलाफ मजबूती से एकजुट हो रहे हैं जो भाजपा को हरा सकता है। इंडिया जैसा बड़ा गठजोड़ उनके चुनाव को आसान बना सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा और भूराजनीतिक हालात 2019 से काफी अलग हैं। हमें स्पष्टता के लिए यह बताना होगा कि भारत की कमजोरी के कोई संकेत नहीं हैं बल्कि वह 2019 की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है और वैश्विक स्तर पर उसका कद बढ़ा है। दरअसल दुनिया बदल गई है। पुलवामा कांड के बाद की गई कार्रवाई या किसी पड़ोसी देश के बहाने अपने देश में राष्ट्रवादी भावना भड़काने की कार्रवाई को आसानी से नहीं झेलने वाले पाकिस्तान ने आर्थिक मोर्चे पर लगभग समर्पण कर दिया है। उसका राजनीतिक संकट भी गहरा हो गया है। ऐसे में उसके भड़काऊ कार्रवाई करने की संभावना कम ही है।

चीन से निपटने को लेकर मोदी सरकार सावधान और शांत

उधर चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लद्दाख तथा अन्य स्थानों पर गतिविधियां तेज कर रहा है। एक ओर जहां पाकिस्तान सीमा पर किसी नई हरकत के लिए बहुत कमजोर है, वहीं चीन हमें भड़काने की स्थिति में है। पाकिस्तान के खिलाफ तो हम कुछ भी करके जीत की घोषणा कर सकते हैं लेकिन चीन के साथ यह सुविधा नहीं है। यही वजह है कि मोदी सरकार चीन से निपटने को लेकर इतनी सावधान और शांत रही है। अब जबकि चीन ने जानबूझकर पिछले जाड़ों में बाली में शी चिनफिंग और मोदी की मुलाकात को लेकर भेद खोल दिया है तो हम देख सकते हैं कि कैसे चीन को शांत करने के लिए पहल की जा रही है। यह विदेश नीति संबंधी वही कदम है जिसके बारे में मैंने आलेख के आरंभ में कहा कि हम इस विषय पर बाद में लौटेंगे। चुनाव के पहले चीन द्वारा कोई भड़काऊ कदम भारत की सुरक्षा के लिए खतरा होगा और वह सरकार के लिए एक बड़ी चुनावी चुनौती भी होगा क्योंकि वह स्वयं को आजाद भारत के इतिहास में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से सबसे मजबूत बताती है।

यह संभव है कि मोदी ने पहले ही सुलह का प्रयत्न किया हो लेकिन उसे गोपनीय रखा गया हो। उसके बाद चीन ने जोहानीसबर्ग में अजीत डोभाल और वांग यी के बीच हुई बैठक में पढ़े गए पर्चे के मंदारिन संस्करण में बदमाशीपूर्वक बाली का जिक्र शामिल कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पहले इसे सौजन्य भेंट करार दिया था लेकिन अब उसे बहुत असहजतापूर्वक यह स्वीकार करना पड़ा कि यह एक महत्त्वपूर्ण बात थी। यह मसला जितना कूटनीति का है उतना ही घरेलू राजनीति का भी। विपक्ष इस समय अपने अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी में है। प्रधानमंत्री इसको लेकर चिंतित नहीं हैं और देश में ऐसा प्रस्ताव कभी कामयाब नहीं रहा है। एक बार अवश्य एक सरकार ने इसका सामना करने के पहले इस्तीफा दे दिया था। इंदिरा गांधी ने बतौर प्रधानमंत्री 16 सालों में 15 अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया था। भारतीय राजनीति हमें बताती है कि असली लड़ाइयां तब होती हैं जब सरकार विश्वास मत पाने की कोशिश करती है। वाजपेयी को ऐसे दो मौकों पर हार का सामना करना पड़ा था और मनमोहन सिंह संप्रग सरकार के दो कार्यकालों में दो बार बहुत करीबी मामलों में बच निकलने में कामयाब रहे थे। उनका पहला विश्वास प्रस्ताव नाभिकीय समझौते के अवसर पर आया और सरकार जाते-जाते बची। दूसरी चुनौती बहुब्रांड खुदरा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अवसर पर आई जो तुलनात्मक रूप से आसान थी।

आमतौर पर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के लिए अवसर होता है कि वह स्पष्ट रूप से निर्धारित समय में बहस कर सके और ऐसे मौकों पर प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया भी तय होती है। इस लिहाज से यह बहुत बड़ा अवसर है। हालांकि मोदी को इससे बहुत अधिक परेशानी नहीं होगी क्योंकि मौकों का लाभ लेने में उनसे बेहतर कोई नहीं है। हालांकि इस बार चिंता जरूर होगी। यह चिंता इस बात में निहित है कि इस बार एकजुट विपक्ष इस अवसर का लाभ अपनी एकजुटता को बढ़ाकर प्रस्तुत करने के लिए करेगा। बीते दशकों के दौरान आम धारणा ऐसी बनी है जहां विपक्षी नेताओं की एकजुटता दिखाती हुई सामूहिक तस्वीरों का मजाक उड़ाया जाता है। संसद में एकजुट होकर हमला करने से उनके एकता के दावों को बल मिलेगा। यह 'इंडिया' के लिए अपनी ब्रांड छवि चमकाने का भी अवसर होगा। मोदी और शाह की राजनीति की बात करें तो वे किसी भी राजनीतिक चुनौती या चुनाव को हल्के में नहीं लेते। बहरहाल अब विपक्षी एकता, विभिन्न राज्यों में भाजपा विरोधी मतों की एकजुटता और जटिल भूराजनीतिक परिदृश्य ने उनकी चुनौती बढ़ा दी है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

दव्युपनिषद् (भाग-4)

गतांक से आगे...

ब्रह्मविद्या की प्राप्ति हेतु हम सदैव आपका ध्यान करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। अज्ञानरूपी रज्जु की सुदृढ़ गाँठ को खोलकर आप हमें मुक्ति प्रदान करें। जो (देवी) हृदय-कमल के मध्य में विराजमान रहती हैं, जो प्रातः काल के सूर्य की भाँति प्रभावाली, पाश एवं अंकुश धारण करने वाली, सौम्यरूपा, वर एवं अभय मुद्राओं से युक्त हाथ वाली, तीन नेत्रों से युक्त, लाल परिधान वाली तथा भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली हैं। हे देवि! आप महान् भय का विनाश करने वाली, महासंकट को शान्त करने में समर्थ एवं महान् करुणामयी हैं, मैं आपकी वन्दना करता हूँ।

जिन (देवी) के स्वरूप को ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, इस कारण उन्हें अज्ञेया कहा गया है। जिनका अन्त नहीं होता, अतः वे अनन्ता (अन्तरहित) हैं। जिनका स्वरूप दृष्टिगोचर नहीं होता, इस कारण उन्हें अलक्ष्या कहते हैं। जिनके जन्म का अता-पता नहीं, इसलिए उन्हें अजा कहा जाता है जो एकाकी ही सर्वत्र विद्यमान रहती हैं, इस कारण उन्हें एका कहते हैं। जो अकेले ही विश्वरूप में विद्यमान हैं, इसलिए उन्हें नैका कहा गया है। अतः वे इन्हीं कारणों से अज्ञेया, अनन्ता, अजा, एका और नैका के नाम से जानी जाती हैं।

वे (देवी) समस्त मंत्रों में मातृका अर्थात् मूलाक्षर में प्रतिष्ठित हैं और शब्दों में ज्ञान रूप से स्थित हैं ज्ञान में चिन्मयातीता रूप में और शून्यों में शून्यसाक्षिणी के रूप में रहती हैं। जिनके अतिरिक्त और कुछ भी श्रेष्ठतम नहीं है, ऐसी वे दुर्गादेवी के नाम से प्रख्यात हैं। उन दुराचार का शमन करने वाली, दुर्विज्ञेया एवं भव सागर से पार उतारने वाली दुर्गादेवी को जगत् से भयभीत हुआ में प्रणाम करता हूँ। इस अथर्वशीर्ष के मन्त्रों का जो मनुष्य पाठ करता है, वह पाँचों अथर्वशीर्षों के जप करने का फल- प्राप्त कर लेता है। इस अथर्वशीर्ष को न जानकर जो मनुष्य अर्चा (प्रतिमा को) स्थापित करता है, वह सैकड़ों- लाखों जप करके भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता है। (वैसे) 108 बार जप करना ही इस पुरश्चरण की विधि कही गई है। जो पुरुष इस उपनिषद् का दस बार भी पाठ कर लेता है, वह उसी क्षण अपने दुष्कृतों (पापों से मुक्त होकर महादेवी की कृपा से महान् से महान् दुष्कर कठिनाइयों मुसीबतों से पार हो जाता है। इस (उपनिषद्) का प्रातः कालीन वेला में पाठ करने से रात्रि में किये हुए पापों का और सायंकाल में पाठ करने से दिन में किये गये दुष्कृत्यों का शमन हो जाता है।

क्रमशः ...

मुस्लिम महिला अधिकार दिवस

मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भारत में 1 अगस्त को मनाया जाता है। तीन तलाक कानून के लागू होने के उपलक्ष्य में 1 अगस्त को पूरे देश में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। शरीयत या मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार, मुस्लिम पुरुषों को लगातार तीन बार तलाक शब्द का उच्चारण करके अपनी शादी को समाप्त करने का विशेषाधिकार दिया गया था। हालांकि, 2019 में भारत सरकार ने इस कानून को निरस्त कर दिया।

भारत की केंद्र सरकार ने 01 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक के खिलाफ एक सख्त कानून बनाया जिसके अनुसार तत्काल या ट्रिपल तलाक को एक आपराधिक अपराध घोषित किया गया था। नए कानून का भारत में सभी महिलाओं, विशेषकर मुस्लिम महिलाओं ने स्वागत किया और तब से 01 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है।

ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून के अधिनियमन को पहचानने और सम्मान करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। ट्रिपल तालक नियम को भारत सरकार द्वारा 2019 के अधिनियम, विवाह अधिकारों के संरक्षण के तहत अवैध घोषित किया गया है। मुस्लिम महिलाएं इस दिन को बेहद खुशी के साथ

मनाती हैं और कानून का तहे दिल से स्वागत करती हैं।

अगस्त का महीना इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। आठ अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 20 अगस्त सद्भावना दिवस और पांच अगस्त अनुच्छेद 370 खत्म होने के लिए जाने जाते हैं। अब एक अगस्त भी मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक की कुप्रथा से मुक्त करने के मामले में भारत के इतिहास में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में दर्ज हो गया है।

तीन तलाक या तलाके बिद्दत न संवैधानिक तौर से ठीक था, न इस्लाम के नुक्तेनजर से जायज था, फिर भी हमारे देश में मुस्लिम महिलाओं का उत्पीड़न करने वाली यह कुप्रथा वोट बैंक के सौदागरों के सियासी संरक्षण में फलती-फूलती रही। 18 मई, 2017 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद मोदी सरकार ने एक अगस्त, 2019 को संसद में कांग्रेस, वाम दलों, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस सहित तमाम कथित सेक्युलर दलों के विरोध के बावजूद तीन तलाक कुप्रथा को खत्म करने के विधेयक को कानूनी रूप दिया। इसी के साथ देश की मुस्लिम महिलाओं के लिए यह दिन संवैधानिक, मौलिक, लोकतांत्रिक एवं समानता के अधिकारों का दिन बन गया।

तीन तलाक के खिलाफ कानून तो 1986 में भी बन सकता था, जब शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया था। उस समय लोकसभा में अकेले कांग्रेस सदस्यों की संख्या 545 में से 400 से ज्यादा और राज्यसभा में 245 में से 159 थी, पर राजीव गांधी सरकार ने पांच मई, 1986 को इस संख्या बल का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी बनाकर मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को कुचलने और तीन तलाक कुप्रथा को ताकत देने के लिए किया। कांग्रेस ने कुछ कट्टरपंथियों के दबाव के आगे घुटने टेककर मुस्लिम महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का आपराधिक पाप किया। कांग्रेस के लम्हों की खता मुस्लिम महिलाओं के लिए दशकों की सजा बन गई। मौखिक रूप से तीन बार चिट्ठी, फोन, वाट्स एप मैसेज के जरिये तलाक बोलकर तलाक देने के मामले सामने आने लगे। ये मामले किसी भी संवेदनशील देश-समावेशी सरकार के लिए अस्वीकार्य थे।

सीमा पर तनाव पर दुनिया भारत के साथ

हर्ष वी. पंत

पिछले हफ्ते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की बाली में हुई बातचीत को लेकर चीन का बयान आया। यह सम्मेलन पिछले साल हुआ था। इसके करीब आठ महीने बाद उसका जिक्र करके चीन कह रहा है कि वहां प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी के बीच जो बात हुई थी, उसमें कहा गया था कि आपसी संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश की जाएगी। इतने महीने बाद इस बात का जिक्र करने के कई अर्थ लगाए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 2020 में गलवान में दोनों देशों के फौजियों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से भारत की स्पष्ट नीति रही है, जिसके बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर कह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि भारत और चीन के संबंध सामान्य नहीं हैं। वे सामान्य तब तक नहीं हो सकते, जब तक चीन सीमा पर मार्च 2020 से पहले वाली यथास्थिति न बनाए।

पिछले हफ्ते ब्रिक्स की मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के नए विदेश मंत्री वांग यी से भी यही कहा कि 2020 से भारत-चीन सीमा पर जो स्थिति है, उसने दोनों देशों के बीच भरोसे को धीरे-धीरे खत्म कर दिया है। दूसरी ओर चीन कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। चीन की आर्थिक हालत उतनी अच्छी नहीं है। जो भी डेटा आ रहे हैं, उनसे पता चलता है कि उसकी इकॉनमी धीमी रफ्तार से बढ़ रही है। चीन में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। चीन की सरकार अंदरूनी समस्याओं से भी जूझ रही है। कुछ समय पहले जिन्हें विदेश मंत्री

बनाया गया था, वह अचानक गायब हो गए। उनकी जगह दूसरे विदेश मंत्री ने पद संभाला है। इन वजहों से वह परेशान है और बैकफुट पर है। चीन के साथ परसेप्शन की भी समस्या है। उसे आक्रामक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है, जिसे वह बदलना चाहता है।

चीन से तुलना करें तो भारत न सिर्फ आर्थिक तौर पर अच्छा कर रहा है, बल्कि एक तरह से दुनिया में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। बाकी देश उसके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चीन इस बात से परेशान होगा कि उसके मुद्दे पर भारत का नैरेटिव ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। भारत कह रहा है कि सीमा पर संबंध सामान्य नहीं हैं, तो चीन यह दिखाना चाह रहा है कि हालात बिलकुल सामान्य हैं। संबंधों को सामान्य करने की जिम्मेदारी भारत पर डालकर वह दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह एक शांत और स्टेबल पावर है। लेकिन सचाई यह है कि वह भारत के लिए हर तरफ से परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। जो बॉर्डर एरिया हैं, वहां लगातार अपनी सेना बनाए हुए है। सीमा क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाता जा रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बीते हफ्ते ही चीन के सामने यह मुद्दा उठाया कि उसने अरुणाचल के एथलीटों को स्टेपल वीजा दिया है। यह दिखाने के लिए कि वह अरुणाचल को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानता है, उसे भारत का अंग नहीं मानता। अगर चीन वाकई भारत के साथ संबंध सुधारने का पक्षधर होता तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, उनको थोड़ा कम करता।

बहरहाल, चीन के साथ और भी मुद्दे हैं, चाहे वह जापान का मामला हो या ताइवान का। मगर ये देश अपनी बात उतने प्रबल तरीके से नहीं रख पाते। वहीं, भारत पूरी सैन्य क्षमता के साथ सीमा पर खड़ा है और चीन को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी भारत ने जिस तरह से अपनी एंगेजमेंट्स बढ़ाई हैं, उसे देखते हुए चीन चिंतित है। इसलिए ऐसा बयान देकर भारत को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है।

उसकी इन तमाम कवायदों का आखिर मतलब क्या है? वह यही तो दिखाना चाहता है कि भारत के प्रधानमंत्री भी चाह रहे थे, इस समस्या का समाधान हो। लेकिन यह बात तो भारत 2020 से कह रहा है कि संबंध सामान्य बनें। सवाल यह है कि किसकी शर्तों पर बनें। आप कनपटी पर बंदूक रखकर तो यह नहीं कह सकते कि जैसा हम चाहें, वैसा करो। या बॉर्डर की जो समस्या है उसे ऐसे हमारे पक्ष में ही हल करो। भारत ने तो यह बात पहले ही स्पष्ट कर दी है कि अगर किसी को पहला कदम उठाना है तो वह है चीन, क्योंकि चीन ने स्टेटस में इकतरफा ढंग से बदलाव करके पुराना फ्रेमवर्क और अंडरस्टैंडिंग तोड़ी है। जब तक भारत में यह विश्वास नहीं आएगा कि चीन भरोसेमंद साथी है, तब तक उससे ईमानदार बातचीत नहीं हो सकती।

यह बात भारत ने हर तरह से साफ की है। अभी जब स्ष्ह्र समिट हुआ, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्ट एंड रोड इनीशटिव को लेकर यह बात कही थी कि कनेक्टिविटी तो हम सब चाहते हैं लेकिन कनेक्टिविटी किसी की संप्रभुता पर खतरा ना बने, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। चीन जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इकॉनमिक कॉरिडोर बना रहा है, भारत उस पर पहले से आपत्ति जता रहा है। भारत की रणनीति एकदम साफ रही है, अब यह चीन पर है कि वह उसे किस तरह से लेता है।

बापू की दिनचर्या

आचार और व्यवहार (भाग-2)

गतांक से आगे...

वे उन्हें सांसारिकता में रहने की दशा में ही आचरण के माध्यम से पावन बनने की प्रेरणा दिया करते। इस प्रकार व्यष्टि और समष्टि नीचे से ऊपर उठता। बौद्धकालीन महाकवि अश्वघोष ने सौंदरानंद महाकाव्य में बौद्ध-धर्म में दीक्षित दंपती का चित्रण किया है। वह कितना मार्मिक और संसार के विकास में बाधक है! जीवन की मधुमय आकांक्षाओं को हृदय-पेटिका में सँजोये, हलदी के पीले हाथवाली षोड़शी ललना और उसके संपूर्ण जीवन की बागडोर को अपने वश में किए यौवन की अरुणिमा से ओतप्रोत विह्वल युवक- दोनों उस युग के महान नेता तथागत से प्रेरणा पाकर अपनी उठती हुई कुसुम-कोमल उमंगों पर शिला रख मुंडित होते और क्षण भर में जनक-जननी को मूच्छित छोड़ घर से निकल जाते हैं। राजपथ के चौराहे पर पहुँचकर एक कहता है- प्रिये! और दूसरी ओर से ध्वनि निकलती है-कहो, प्राण! अब हाथ छोड़ो और अपना रास्ता लो। महान नेता तथागत के उपदेशों से उत्पन्न आवेश अभी दोनों में कार्यरत था। सुनकर ललना के अंतःकरण में छिपा पौरुष-भाव जाग उठा। उसने हलदी से रँगी अपनी उँगलियों का संकेत कर कहा-तो, प्रियतम! तुम्हारा मार्ग भी तो यह है- जाओ । और, दोनों एक-दूसरे को देखे बिना ही दो दिशाओं की ओर सदा के लिए चल पड़े। उस समय समीप के पेड़-पौधे, लता-गुल्म तथा पशु-पक्षी सभी करुणा की गुहार कर मौन हो गए! बुद्ध अपनी प्रेयसी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोते छोड़ चुपचाप चल थे। यशोधरा बुद्ध के प्रतिबिंब राहुल को गोद में लिए-लिए %सखि, वे मुझसे कहकर जाते की रट लगाकर क्षीण कलेवरा होती गई। उस युग के युवक-युवतियों को उन्होंने अपने अनुरूप ढालने की कोशिश की। बापू ने दक्षिण अफ्रीका या भारत जहाँ कहीं भी जन-जागरण किया, नर-नारी को समष्टि रूप में देखा और सदा साथ रहने की शिक्षा दी।

क्रमशः ...

ज्ञानवापी पर मुस्लिम समाज ऐतिहासिक गलती मानते हुए प्रस्ताव लाये : योगी आदित्यनाथ

नोएडा। ज्ञानवापी मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा था। मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखा है ना। ज्योर्तिलिंग है देव प्रतिमाएं हैं। दीवारें चिल्ला-चिल्लाकर क्या कह रही हैं। उधर, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए इसे विवाद को हवा देने वाला बयान बताया।

सीएम योगी ने कहा कि मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। दरअसल, मुख्यमंत्री योगी एएनआई के पॉडकास्ट में अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान ज्ञानवापी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने बड़ा बयान दिया।

इस दौरान एक और अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने

कहा कि देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। देखिए मैं ईश्वर का भक्त हूं, लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं करता हूं। आपका मत, आपका मजहब, अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा। अपनी मस्जिद, अपने इबादतगाह तक होगा। सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए नहीं और इसको आप जो है किसी भी अन्य तरीके से दूसरे पर थोप नहीं सकते। नेशन फर्स्ट। अगर देश में किसी को रहना है तो राष्ट्र को सर्वोपरि मानना है, अपने मत और मजहब को नहीं।

वहीं, ज्ञानवापी को लेकर सीएम योगी के बयान का संत समाज ने स्वागत किया है। अखिल भारतीय संत समिति महामंत्री स्वामी जितेन्द्रानंद सरस्वती कहा कि ज्ञानवापी का संघर्ष लंबा हो चला है, मुस्लिम समाज को पहल करने की जरूरत है।

स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया पलटवार

सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सभी धार्मिक स्थलों की 15 अगस्त 1947 की स्थिति को यथास्थिति स्वीकार किया जाए। मस्जिद में मंदिर खोजने का दुस्साहस कर रहे लोग इस विवाद हो हवा दे रहे हैं। विवाद को आगे बढ़ाने की प्रथा शुरू कर रहे है, ऐसा ही चलता रहा तो इसी प्रथा के तहत कल लोग मंदिरों में बौद्ध मठ खोलना शुरू कर देंगे।

ज्ञानवापी मामले पर योगी के बयान पर ओवैसी का पलटवार

योगी आदित्यनाथ के बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी पलटवार किया है। अपने बयान में ओवैसी ने कहा कि मुख्यमंत्री यह जानते हैं कि मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एएसआई सर्वे का विरोध किया है। इस मामले में कुछ दिन में फैसला भी सुनाया दिया जाएगा। फिर भी उन्होंने इस तरह का बयान दिया है, यह न्यायिक अतिरेक है। इसके साथ ही ओवैसी ने 1991 के एक्ट का भी जिक्र किया। ओवैसी ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वॉरशिप एक्ट को सभी को मानना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसे नकार नहीं सकते। उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री हैं, आपको कानून को पालन करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि योगी को पढ़ना चाहिए कि विवेकानंद ने ओडिशा के एक मंदिर को लेकर क्या कहा था। आप कानून का पालन नहीं करना चाहते। आप मुसलमानों पर दबाव डालना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस जगह 400 साल से मंदिर है, आप उस जगह पर दबाना चाहते हैं। ओवैसी ने कहा कि आप 400 साल पीछे जाना चाहते हैं या फिर देश को 100 साल आगे ले जाना चाहते हैं।

सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 पर सुनवाई से पहले अमित शाह ने दिये बड़े संकेत

भोपाल। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाये जाने के विरोध में दायर की गयी याचिकाओं पर सुनवाई से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अनुच्छेद 370 को हटाया जाना मोदी सरकार की एक बड़ी कामयाबी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में रविवार को भाजपा की एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने (जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले) अनुच्छेद 370 को 70 साल तक गोदी में अपने बच्चे की तरह पाल कर रखा था, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अनुच्छेद हटाकर कश्मीर को भारत के साथ जोड़ दिया।

हम आपको बता दें कि प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पांच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ दो अगस्त से जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले, अमित शाह का यह बयान दर्शा रहा है कि सरकार अपने फैसले के विरोध में दायर याचिकाओं का पुरजोर विरोध करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों के खिलाफ 'सर्जिकल स्ट्राइक' और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण सरीखे मामलों में भी मोदी सरकार के कदमों की सराहना की। उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, 2004 से 2014 के बीच संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार में पाकिस्तान से आतंकी (भारत) आते थे और वारदातों को अंजाम देकर चले जाते थे, लेकिन तब केंद्र की सरकार उफ्फ तक नहीं करती थी। शाह ने लोगों से पूछा, ''कांग्रेस अपना नाम बदल ले, फिर भी क्या आप इस पार्टी को वोट दे सकते हैं?'' हम आपको याद दिला दें कि केंद्र सरकार ने पांच अगस्त 2019 को पूववर्ती जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लेते हुए राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। सरकार के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं न्यायालय में दायर की गयीं, जिन्हें अदालत की संविधान पीठ के पास सुनवाई के लिए भेज दिया गया था। 11 जुलाई को शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को वापस लेने के फैसले को चुनौती देने वाले विभिन्न आवेदनों पर दो अगस्त से रोजाना सुनवाई की जाएगी।

पीएमएल-एन सत्ता में लौटने पर नवाज होंगे पीएम : शहबाज

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में वित्त मंत्री इशाक डार की नियुक्ति की संभावना से इनकार करते हुए कहा कि आगामी आम चुनावों को पारदर्शी बनाने के लिए अगले महीने अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए एक तटस्थ व्यक्ति का चयन किया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) पार्टी के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने संकेत दिया कि 2019 से लंदन में स्व-निर्वासित निर्वासन में रह रहे तीन बार के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अगले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान लौट आएंगे।

उन्होंने कहा कि अगर पार्टी चुनाव जीतती है तो 73 वर्षीय पीएमएल-एन सुप्रीमो प्रधानमंत्री होंगे। उन्होंने जियो न्यूज को बताया कि नेशनल असेंबली (एनए) के विघटन की अधिसूचना संसद के निचले सदन का कार्यकाल पूरा होने से कुछ दिन पहले राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को भेज दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एनए 12 अगस्त की रात 12 बजे अपना कार्यकाल पूरा कर लेगा। उन्होंने कहा कि सहयोगी दलों, पीएमएल-एन के सर्वोच्च नेता नवाज शरीफ और नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता राजा रियाज के साथ परामर्श के बाद कार्यवाहक व्यवस्था पर

सहमति होगी। शहबाज़ ने अपने गठबंधन सहयोगियों से सहमति जताते हुए कहा कि इस पद पर एक तटस्थ व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि कोई भी चुनाव के नतीजों पर सवाल न उठा सके। उन्होंने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र में एक बहुत ही कुशल अंतरिम सरकार होगी। उन्होंने कहा कि पीएमएल-एन सहयोगी दलों के साथ सीटों का समायोजन करने की कोशिश करेगी, साथ ही कहा कि पार्टी उन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारेगी जहां वे आम सहमति तक नहीं पहुंच पाएंगे। कार्यवाहक ढांचे को नीतिगत निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने वाला एक विधेयक हाल ही में संसद द्वारा पारित किया गया था। शहबाज ने यह भी कहा कि पीएमएल-एन सुप्रीमो नवाज शरीफ को पाकिस्तान लौटने पर कानून का सामना करना पड़ेगा।

खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती बम विस्फोट के पीछे इस्लामिक स्टेट का हाथ

पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की पुलिस ने सोमवार को कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि एक कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी के राजनीतिक सम्मेलन में हुए आत्मघाती विस्फोट के पीछे प्रतिबंधित आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट (आईएस) का हाथ है। इस विस्फोट में कम से कम 44 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। यह विस्फोट रविवार को हुआ था, जब कट्टरपंथी जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (जेयूआई-एफ) के 400 से अधिक सदस्य खार शहर में एक सभा के लिए एकत्रित हुए थे। इस शहर की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। 'जियो न्यूज' ने पुलिस अधिकारियों के हवाले से कहा, ''हम बाजौर विस्फोट की अब भी जांच कर रहे हैं और उसके बारे में सूचना जुटा रहे हैं। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि इसके पीछे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट का हाथ है।'' पुलिस के मुताबिक, वह आत्मघाती हमलावर के बारे में जानकारी जुटा रही है, जबकि बम निरोधक दस्ता घटनास्थल से सबूत एकत्रित कर रहा है। जिला पुलिस अधिकारी नजीर खान ने बताया कि तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। प्रांतीय पुलिस प्रमुख अख्तर हयात खान के अनुसार, विस्फोट को अंजाम देने के लिए 10 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने बताया कि हमलावर राजनीतिक सम्मेलन में शामिल लोगों में से एक था और वह पहली पंक्ति में बैठा हुआ था। स्थानीय पुलिस के मुताबिक, हमलावर ने सम्मेलन के मंच के पास खुद को विस्फोटक से उड़ा लिया। पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विस्फोट जेयूआई-एफ नेता मौलाना अब्दुल रशीद के मंच पर पहुंचने के तुरंत बाद हुआ।

दुश्मन देश पर हमला करने पहुंचे भारत के रॉकेट

प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ 3 देशों के उड़ा दिए होश

नईदिल्ली। भारत ने ऐसा कदम उठाया है जिसने एक साथ कई देशों को परेशान कर दिया है। भारत के एक कदम से तीन दुश्मन देश बर्बाद होने वाले हैं। भारत ने अपने वादे को पूरा करते हुए एक छोटे से देश अर्मेनिया को खतरनाक पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम दे दिया है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान का दोस्त अजरबैजान काफी खौफ में नजर आ रहा है। रूस यूक्रेन वॉर से पहले अर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध दुनिया ने देखा था। इस युद्ध में पाकिस्तान खुलकर अजरबैजान के साथ खड़ा था। जिसके बाद अर्मेनिया ने भारत के साथ दो हजार करोड़ का हथियार सौदा किया है। इसी के तहत भारत का पिनाका अर्मेनिया में पहुंच गया है। अजरबैजान भारत से अर्मेनिया को हथियार देने का विरोध जाहिर कर रहा है।

भारत का प्रलंयकारी स्वदेशी मल्टीबैरल रॉकेट सिस्टम पिनाका जिसकी तुलना अमेरिकी हैमर्स से की जाती है। उसकी डिलीवरी अर्मेनिया को हो चुकी है। इस खबर से पाकिस्तान के टॉप फाइव दोस्तों में शामिल अजरबैजान को सबसे बड़ा सदमा लगा है। अब अर्मेनिया पर किसी भी हमले का जवाब भारतीय मल्टीबैरल रॉकेट सिस्टम पिनाका देगा। जिसका सीधा सा मतलब अर्मेनिया के दुश्मनों की तबाही होगी। अर्मेनिया लगातार अजरबैजान को दुनियाभर के देशों से मिल रहे हथियारों की वजह से परेशान था। जिसके बाद उसने भारत के साथ 2 हजार करोड़ रुपए के हथियारों का सौदा किया था। इसी सौदे में शामिल पिनाका की पहली खेप अर्मेनिया पहुंच चुकी है।

अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच काफी समय से जंग चल रही है। अजरबैजान तुर्की और पाकिस्तान की मदद से अर्मेनिया पर हमले कर रहा था। लेकिन अब भारत ने अर्मेनिया को आत्मरक्षा के लिए अपना खतरनाक पिनाका रॉकेट सिस्टम दे दिया। भारत ने अर्मेनिया को जो पिनाका रॉकेट सिस्टम भेजा है वो 40 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इस तरह से भारत ने एक तीर से चार शिकार किए हैं। सबसे पहला तो भारत के हथियारों पर अब दुनिया को भरोसा हो रहा है। वहीं दूसरा, तीसरा और चौथा शिकार अजरबैजान, पाकिस्तान और तुर्की हैं। ये तीनों ही देश भारत के खिलाफ कश्मीर को लेकर संयुक्त राष्ट्र में अपना एजेंडा चलाते हैं। लेकिन अर्मेनिया की मदद करके भारत ने तीनों को एक साथ जवाब दिया है।

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने अध्यादेश बिल के विरोध को गलत बताया

- **ये बिल सदन में पास होना चाहिए, ये बिल दिल्ली की स्थिति के मुताबिक है**

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र में केंद्र के दिल्ली सेवा अध्यादेश को बिल के रूप में पेश किया जाना है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां इसे किसी भी हाल में पास करवाने के लिए कमर कस चुकी है वहीं विपक्ष इसे किसी भी सूरत में राज्यसभा में पारित नहीं होने देना चाहता। इस मामले में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का साथ देते हुए बिल का विरोध करने की बात कही थी। लेकिन अब कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे विपक्षी एकता को झटका लग सकता है।

संदीप दीक्षित ने इस मामले पर कहा, लोकसभा में बीजेपी के पास बहुमत है, ये बिल सदन में पास होना चाहिए। ये बिल दिल्ली की स्थिति के मुताबिक है। अगर आप दिल्ली को

शक्तियां देना चाहते हैं तो ये पूर्ण राज्य बनाया जाना चाहिए। मेरी राय में इस बिल का विरोध करना गलत है।

बता दें कि दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश अगर संसद के दोनों सदनों में पास हो गया तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा। यही कारण है कि पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसदों के लिए नोटिस जारी कर कहा है कि सोमवार 31 जुलाई, मंगलवार 1 अगस्त, बुधवार 2 अगस्त, गुरुवार 3 अगस्त और शुक्रवार 4 अगस्त 2023 को राज्यसभा में अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाएंगे जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 शामिल है। पार्टी ने सभी सांसदों से अनुरोध किया है कि वह सदन में मौजूद रहें।

इससे पहले कांग्रेस ने साफ किया था कि वह दिल्ली की प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश का संसद में समर्थन नहीं करेगी। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसकी घोषणा की थी। कांग्रेस के इस ऐलान के बाद ही आम आदमी पार्टी ने विपक्ष के गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए राजी हुई थी।

बता दें कि बिल के प्रावधानों के तहत नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के गठन का प्रस्ताव है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अथॉरिटी के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव इसके सदस्य होंगे।

दिल्ली सर्विस बिल को लेकर 4 अगस्त तक हो सकता है फैसला

नईदिल्ली। संसद भवन में इस समय मानसून सत्र चल रहा है जिसमें दिल्ली सर्विस बिल और मणिपुर हिंसा को लेकर हंगामे के आसार तेज है। इस बीच, केंद्र के अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के बीच तनातनी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को अपने सभी राज्यसभा सांसदों को विधेयक पर पार्टी के रुख का समर्थन करने के लिए 31 जुलाई से 4 अगस्त तक सदन में उपस्थित रहने के लिए तीन-लाइन व्हिप जारी किया। संसद के मानसून सत्र में सरकार द्वारा सदन में लाए जाने पर दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश को प्रतिस्थापित किया जाएगा। इस बिल का दिल्ली की सरकार और आम आदमी पार्टी लगातार विरोध कर रही है। पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसदों के लिए नोटिस जारी कर कहा है कि सोमवार 31 जुलाई, मंगलवार 1 अगस्त, बुधवार 2 अगस्त, गुरुवार 3 अगस्त और शुक्रवार 4 अगस्त 2023 को राज्यसभा में निम्नलिखित अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाएंगे जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 शामिल है। इसे लेकर सभी से अनुरोध है कि वह सदन में मौजूद रहें। गौरतलब है कि दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश की जगह लेने वाला विधेयक अगले सप्ताह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सरकार के एजेंडे में है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा को सूचित किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023, को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है। मई में केंद्र द्वारा लाया गया अध्यादेश, जिसने सेवाओं को दिल्ली विधान सभा की विधायी क्षमता से बाहर कर दिया। मालूम हो कि यह अध्यादेश दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ दिनों बाद लाया गया था।

चुनावी वर्ष में सिर्फ राजनीति कर रहा विपक्ष : अनुराग ठाकुर

नईदिल्ली। मणिपुर मामले को लेकर संसद में जबरदस्त तरीके से तकरार जारी है। एक और विपक्षी जहां मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहा है तो वहीं सरकार भी साफ तौर पर कह रही है कि वह चर्चा को तैयार है। बावजूद इसके तकरार कम नहीं हो पा रही है। इन सबके बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार-पलटवार का दौर भी जारी है। सत्तापक्ष जहां विपक्षी दलों पर राजनीति का आरोप लगा रही है तो वहीं विपक्षी दलों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग की जा रही है।

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हमने जब उनकी मणिपुर पर चर्चा की मांग को स्वीकार किया तो उन्होंने प्रधानमंत्री के सदन में आकर जवाब देने की मांग रखी। विपक्ष की ज़िम्मेदारी है कि मसला शांतिपूर्ण समाधान की तरफ बढ़े। वे ऐसे मसले पर भी राजनीति कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सदन के अंदर आएं और चर्चा में भाग लें। सरकार पहले दिन से चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ऐसी क्या मजबूरी है कि वे चर्चा से भाग रहे हैं...साफ दिखता है कि वे चुनावी वर्ष में सिर्फ राजनीति करने का काम कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर आपको 2018 की याद हो तो तब भी विपक्ष यह जानते हुए भी कि भाजपा-एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है उसके बाद भी अविश्वास प्रस्ताव लाया था।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्पीकर जब चाहे तब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करे, सरकार चर्चा के लिए तैयार है और देश को भी विपक्ष का असली चेहरा नज़र आए। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि हम चाहते हैं कि आज दोपहर 2 बजे संसद में मणिपुर पर चर्चा हो। वे (विपक्ष) सदस्यों को दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन वे (विपक्ष) पहले ही सदन के 9 महत्वपूर्ण दिन खराब कर चुके हैं।

इंडिया गठबंधन के नेताओं के मणिपुर दौरे का क्या है निचोड़

अंकित सिंह

जातीय संघर्षग्रस्त मणिपुर में जमीनी हालात का मौके पर आकलन करने के लिए विपक्षी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को दो दिवसीय दौरे पर गया था। प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), आम आदमी पार्टी (आप), डीएमके, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), जनता दल-यूनाइटेड (जेडी-यू) और सीपीएम के सांसद शामिल थे। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसदों ने सोमवार को समूह के नेताओं को जानकारी दी। इन सांसदों ने संसद भवन के एक कक्ष में 'इंडिया' के घटक दलों के नेताओं से मुलकात की। इस मौके पर कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता टीआर बालू, समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता रामगोपाल यादव और कई अन्य दलों के नेता मौजूद थे। विपक्षी दलों के गठबंधन 'इंडिया' का एक प्रतिनिधिमंडल 29 जुलाई को हिंसा प्रभावित मणिपुर पहुंचा था। प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मणिपुर की स्थिति को गंभीर बताया। उन्होंने कहा, अगर सत्ताधारी पार्टी का कोई सांसद वहां जाकर खुद स्थिति को देखेगा तो वह आकस्मिक बयान नहीं देगा। मणिपुर से लौटने के बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मणिपुर के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली और देश के बाहर भी बड़ी-बड़ी बातें की जा रही हैं...लोगों के घरों में खाना और दवाइयां नहीं हैं, बच्चों के पास पढ़ने के लिए कोई सुविधा नहीं है, कॉलेज के छात्र कॉलेज नहीं जा सकते। दो समुदायों के बीच लड़ाई को खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है...राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने अपनी आंखें बंद ली हैं।

किसने क्या कहा

मणिपुर से लौटने के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि लोगों ने वहां (मणिपुर) हमारा

स्वागत किया। एनडीए गठबंधन और प्रधानमंत्री मोदी को भी मणिपुर का दौरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वहां लोगों के साथ जो हुआ उससे हम निराश हैं। राज्यपाल से मुलाकात में हमने सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल यहां आये, हम पहले दिन से यही सुझाव दे रहे हैं लेकिन पीएम गायब हैं। उनके मंत्री दिल्ली में बैठकर बयान दे रहे हैं। उन्हें वहां की जमीनी हकीकत देखने के लिए मणिपुर का दौरा करना चाहिए।

राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि हम चाहते हैं कि मणिपुर में शांति बहाल हो। हमारी एकमात्र मांग है कि दोनों समुदाय सद्भाव से रहें। मणिपुर में स्थिति खौफनाक, दर्दनाक और पीड़ादायक है। संसद में पहले ही चर्चा हो चुकी है कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को मणिपुर का दौरा करना चाहिए।

टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने कहा कि हमने मणिपुर की राज्यपाल से कहा कि हम एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल चाहते थे लेकिन सरकार सहमत नहीं थी इसीलिए I.N.D.I. गठबंधन ने दौरा किया... जब पीएम मोदी संसद में आएंगे तब हम अपनी बात रखेंगे।

जदयू सांसद राजीव रंजन (ललन) सिंह ने कहा कि दोनों समुदायों में असुरक्षा की भावना और विश्वास की कमी है, उन्होंने राज्य सरकार पर विश्वास की कमी व्यक्त की। उनका कहना है 3 मई के बाद से घटनाएं हुईं लेकिन राज्य सरकार ने इसे नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। राज्यपाल ने कहा कि वह सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही हैं लेकिन हम जानते हैं कि राज्यपाल के पास सीमित शक्तियाँ हैं और राज्य को चलाने की शक्ति राज्य सरकार के हाथों में है।

डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा कि हमने राज्यपाल को अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं, वह भी चिंतित हैं और चाहती हैं कि हम केंद्र सरकार को बताएं कि हमने क्या देखा है... हम बहस के लिए कहेंगे और हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हमने क्या देखा है और लोग भी चाहते हैं सभी दलों के नेता वहां (मणिपुर) जाएं और देखें कि क्या हो रहा है...वहां शांति वार्ता होनी चाहिए, यही एकमात्र रास्ता है।

एनसीपी (शरद पवार गुट) सांसद पी.पी. मोहम्मद फैजल ने कहा कि हमने जो कुछ भी देखा और सुना है वह हमारी उम्मीदों से परे है...उन लोगों को हुई पीड़ा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता...अगर सरकार ने शुरू में कार्रवाई की होती तो ऐसी स्थिति से बचा जा सकता था, सरकार मूकदर्शक बनी रही और ठीक से कार्रवाई नहीं की।

सोशल मीडिया मार्केटिंग में कैरियर

इंटरनेट अब आपकी जेब में है। किशोर से लेकर बुजुर्ग तक, हर कोई सोशल मीडिया पर सक्रिय है। एक ओर जहां ऑनलाइन खरीदारी का चलन बढ़ा है, वहीं कंपनियां सोशल साइट्स के जरिए मार्केटिंग करने के नए-नए तरीके खोज रही हैं। यह काम कर रहे हैं सोशल मीडिया मैनेजर्स, जिनकी मांग कॉरपोरेट जगत में बढ़ रही है।

सोशल मीडिया मार्केटिंग इन दिनों करियर के नए विकल्पों में से एक बन कर उभरी है। इस क्षेत्र में तरक्की करने की असीम संभावनाएं हैं। इसके दो कारण हैं। पहला तो यह कि भारत में इस समय 24 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता हैं और दूसरा ये कि भविष्य में इनकी संख्या करीब दस गुना तक बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत में 96 करोड़ लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। सस्ते स्मार्टफोन आने से तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां इस नए ट्रेंड को अनदेखा नहीं कर सकतीं। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अगर किसी कंपनी को टिके रहना है तो उसे इस नए डिजिटल माध्यम द्वारा ग्राहकों की जेब से पैसा निकालना होगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और ना जाने कितनी सोशल साइट्स बजरिये मोबाइल आपकी जेब में हैं। सोशल साइट्स की उपयोगिता को दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां पहले ही भांप गई थीं। यही कारण है कि इन पर अपनी कंपनी या उत्पादों का प्रचार करना उन्होंने कुछ साल पहले से ही आरंभ कर दिया है।

क्या है सोशल मीडिया

सोशल मीडिया मार्केटिंग तमाम सोशल साइट्स के जरिये किसी कंपनी या उसके उत्पाद की मार्केटिंग का काम है। इसके जरिये कुछ लोग या टीम, किसी खास वस्तु को सोशल साइट्स पर लोकप्रिय बना देते हैं, जिससे उसकी बिक्री में बढ़ोतरी होती है। इसमें सबसे अधिक वे सोशल साइट्स लाभदायक हैं, जिन पर ज्यादा ट्रैफिक आता है। ट्रैफिक यानी उस साइट पर निरंतर आने-जाने वाले लोग। अगर आप भी फेसबुक यूजर हैं तो आपने इस तरह के कई विज्ञापन देखे होंगे। पर सोशल मीडिया मार्केटिंग इन विज्ञापनों से कुछ अलग काम है। इसमें सीधे तौर पर मार्केटिंग करने की बजाय किसी मुहिम के तहत ब्रांडिंग की जाती है।

कंपनियों को मिलता है फायदा

सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति या ग्रुप या कंपनी से सीधे बातचीत का मौका देती हैं। ऐसे में जब कोई कंपनी सोशल साइट पर आती है तो लोग उससे जुड़ी शंकाओं को सीधे तौर पर पोस्ट कर सकते हैं। यही कारण है कि सोशल साइट पर उत्पाद को लोकप्रिय होते समय नहीं लगता। उदाहरण के लिए ट्विटर पर री-ट्वीट और री-पोस्ट के विकल्प किसी भी ग्राहक को वृहद नजरिए से उत्पाद को जांचने का और उसे पसंद या नापसंद करने का मौका देते हैं। इससे लोगों की संख्या में इजाफा होता है और कई जानकारियों का भी आदान-प्रदान होता है। यह मार्केटिंग के दूसरे तरीकों से काफी कारगर है। चूंकि हर व्यक्ति को कंपनी खुद जवाब देती है, इसलिए ग्राहक की कंपनी के प्रति विश्वसनीयता भी बढ़ती है।

किन्हें मिलती है वरीयता

इस इंडस्ट्री से जुड़े लोग कहते हैं कि वे ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं, जो सोशल मीडिया को अच्छी तरह समझते हों और लोगों से संवाद बनाना जानते हों। आवश्यक नहीं कि आप मार्केटिंग बैकग्राउंड से ही हों। इसमें आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर, इमर्जिंग मीडिया एंड कंटेंट मैनेजर, सोशल नेटवर्किंग एंड कम्युनिटीज मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर आदि कोई भी पोस्ट मिल सकती है।

लोकप्रियता बढ़ाने का तरीका

इस मार्केटिंग में सिर्फ उत्पादों की लोकप्रियता बढ़ाना ही मकसद नहीं, बल्कि कई अलग नजरियों से भी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए 2008 के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में बराक ओबामा ने ट्विटर और फेसबुक का जम कर इस्तेमाल किया था और इससे उनकी लोकप्रियता में काफी इजाफा हुआ था। समय-समय पर उनके सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल पेजों को अपडेट किया गया और वे लोगों से सीधे जुड़े रहे। इसी का इस्तेमाल पिछले आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था, जिससे सोशल साइट्स पर उनकी लोकप्रियता बढ़ी थी।

कहां-कहां होती है जरूरत

ट्विटर- ट्विटर कंपनियों को अपने उत्पादों को प्रमोट करने के लिए 140 कैरेक्टर की सीमा देता है, जिसमें छोटा ट्वीट लिखा होता है। यह ट्वीट सीधे तौर पर उस उत्पाद की वेबसाइट, फेसबुक प्रोफाइल, फोटो, वीडियो आदि से जुड़ा होता है। हालांकि ट्विटर ने अब शब्द-सीमा बढ़ा कर अधिकतम 1000 कैरेक्टर कर दी है।

यू-ट्यूब- इसमें कंपनियां अपने उत्पाद को वीडियो की सहायता से ग्राहकों तक पहुंचाती हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी ने कुत्ते की ट्रेनिंग पर शोध किया है तो यह संभव है कि उसे यहां ऐसा वीडियो भी मिल जाए। भारत में हर माह आठ करोड़ लोग यू-ट्यूब पर जाते हैं।

फेसबुक- इसमें किसी भी उत्पाद का वीडियो, फोटो या लंबी सी व्याख्या आदि पोस्ट की जा सकती है। यह सीधे तौर पर ट्विटर से लिंक होता है।

गूगल प्लस- यहां उत्पाद के साथ गूगल सर्च इंजन का विकल्प भी होता है, जिससे ग्राहक उसके बारे में और जानकारियां सर्च कर सके।

लिंक्डइन- यह कंपनियों को प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाने की इजाजत देता है। इसमें भी ट्विटर आदि का लिंक अटैच होता है।

इंस्टाग्राम- मई 2014 तक इंस्टाग्राम के 2 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता थे। इंस्टाग्राम कंपनियों को मौका देता है कि वो लोगों से सीधे तौर पर जुड़ सकें और अपनी बात रख सकें।

टंबलर- यह कंपनी को ब्लॉग बनाने को कहता है, जिसके जरिए ग्राहक उससे खुद संपर्क कर सके।

क्या करना होता है काम

इसमें मुख्य तौर पर दो तरह के काम करने होते हैं- प्रमोशन और मॉनिटरिंग। प्रमोशन के तहत सोशल मीडिया के माध्यम से ब्रांड के प्रति लोगों में जागरूकता और बिक्री को बढ़ाना, नए उत्पादों का लॉन्च, री-लॉन्च आदि सब सम्मिलित होता है। मॉनिटरिंग में यह समझना होता है कि लोग ब्रांड को कैसे ले रहे हैं और रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है। जब आप इस काम की शुरुआत करते हैं या नई नौकरी ज्वाइन करते हैं तो आपसे इन कामों की उम्मीद की जाती है-

- प्लानिंग में सहयोग देना।
- एक्टिव होकर लोगों को रिस्पॉन्स करना।
- नए ट्रेंडस को जान कर उस तरह से काम करना। आने वाले प्रोजेक्ट्स में नए ट्रेंड्स का ध्यान रखना।
- इसके अलावा डिजाइन या डेवलेपर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। नए प्रोजेक्ट को यही लोग डिजाइन करते हैं।
- नौकरी की तलाश में ऐसे मिलेगी सफलता सोशल मीडिया मार्केटिंग में कई तरह की एजेंसियां काम करती हैं। इनमें नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं या फिर आप खुद भी यह काम शुरू कर सकते हैं। इसमें आगे बढ़ने के लिए इन बातों को ध्यान रखना आवश्यक है।

[भविष्यफल]

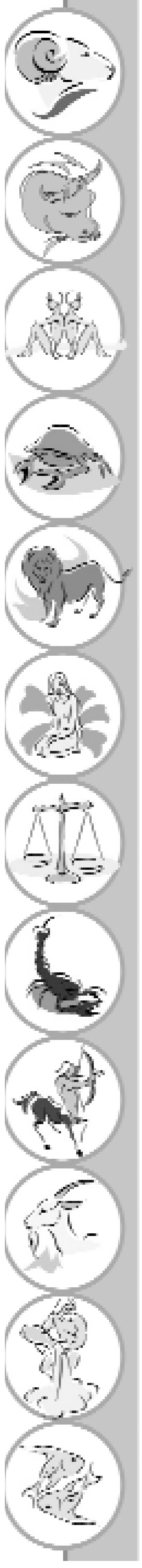

मेष

आज का दिन भाग्यशाली बीतेगा। सामाजिक दायरा बढ़ेगा। घर और बाहर के अव्यवस्थित खाने से बचें। ऑफिस में यदि कोई विरोधी है तो उसके षड्यंत्र से सावधान रहें। आज खर्च भी हो सकता है। घर के छोटे सदस्यों के साथ अधिक वक्त बिताएं। उन्हें आपके सपोर्ट की बेहद जरूरत है।

वृष

आज का दिन खुशगवार बीतेगा क्योंकि दिन शुभ है। अपने प्रेमी से आज मिलन होगा। दिनभर उत्साह बना रहेगा। कुछ असमंजस के कारण मुनाफे के रास्ते में अड़चन आ सकती है। माता पिता का आशीर्वाद बना रहेगा। अनुभवी से सलाह लेने पर मामला सुलझ सकता है। आराम को समय दें।

मिथुन

आज का दिन थोड़ा सावधानी से चलने का है। आसपास के लोगों से बहसबाजी में न उलझें। किसी शुभ मांगलिक कार्य में जाने का मौका मिलेगा। दूसरों की मदद से दिल को सुकून मिलेगा। सेहत सामान्य रहेगी। मनोरंजन पर समय कम खराब करें।

कर्क

आपके लिए आज का दिन सामान्य रिजल्ट देने वाला होगा। रोजगार व्यवसाय में लाभ होगा। ईमानदारी से बनाए गए रिश्ते लंबे समय तक आपका साथ निभाएंगे। कुछ लोगों की किस्मत आज चमक सकती है। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।

सिंह

आज का दिन काफी व्यस्त रहेगा। मेहनत के बाद उसका फल मिल जाएगा। अपने पार्टनर के साथ शाम का स्पेशल प्रोग्राम कामयाब होगा। इज्जत बढ़ेगी और अचानक घूमने-फिरने से कोई फायदा हो सकता है। बच्चों के प्रति चिंता रह सकती है लेकिन सब सकारात्मक ही होगा।

कन्या

आज का दिन खुशगवार बीतेगा। लाभ के मौके मिलेंगे। किसी असरदार शख्स पर पैसा खर्च होगा। जीवन की दिशा नया मोड़ लेगी। यात्रा होगी और जायदाद के कागजों में दस्तावेजों के प्रति सजग रहें। धर्म-कर्म में रूचि बढ़ेगी। मनोरंजन के प्रयास सफल होंगे।

तुला

आपके लिए आज का दिन एक्टिव है। पैसे की परेशानियां सुलझ जाएंगी। हैल्थ से जुड़ी परेशानियां हल हो जाएंगी। कोई समाचार प्राप्त होने के योग है। किसी खास व्यक्ति से परिचय होगा और बिजनेस में फायदा पहुंचेगा। किसी खास चीज के गुम होने का दुख भी हो सकता है।

वृश्चिक

थोड़ी सी मेहनत से ही सम्मान मिलेगा। अच्छे व्यवहार से नए दोस्त बनेंगे और नए प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू हो जाएगा। ऑफिस में खास परिवर्तन होंगे व काम भी बनते नजर आएंगे। मनोरंजन के प्रयास रहेंगे। मित्रमंडली से सहयोग मिलेगा। थकान रह सकती है।

धनु

आज का दिन आपके लिए अच्छा है। राजनीतिक गतिविधियां बढ़ेंगी। किसी अनुभवी व्यक्ति से लाभ उठाएं लेकिन उस पर धन खर्च होगा। जीवन की दिशा नया मोड़ लेगी। प्रॉपर्टी के मामले हल होंगे। अनजान व्यक्ति पर आंखे बंद करके विश्वास न करें।

मकर

छोटे-मोटे झगड़े दिन के पहले हिस्से में सिर उठाएंगे लेकिन आपकी सूझबूझ से जल्द ही निपट जाएंगे। बढ़ते खर्च पर लगाम लगेगी। अधिक मेहनत करेंगे और अपने व्यवहार में सुधार करेंगे तो फायदे में रहेंगे। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

कुंभ

व्यवसाय में लाभ होगा। ऑफिस में काम को धीरे-धीरे ही करेंगे तो फायदे निश्चित हैं। पढ़ाई-लिखाई में ध्यान दें। प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। मेहनत से किए गए काम के अच्छे नतीजे निकलेंगे। ऑफिस में नए साथी काम में हाथ बंटाएंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मीन

आज आपका दिन भाग्यशाली रहेगा। व्यापार और इन्वेस्टमेंट में चिंता खत्म होगी। घूमने फिरने और मनोरंजन का सुख मिलेगा। नए दोस्त बनेंगे। डेली रूटीन और खाने-पीने का पूरा प्रोग्राम व्यवस्थित तरीके से बनाएं।

कैरियर के रनवे पर दौड़ने से पहले...

बहुत से युवा ग्रेजुएशन से पहले ही कोई भी नौकरी शुरु कर खुद को आत्मनिर्भर बना लेते हैं। ऐसी नौकरी भले ही उन्हें कुछ समय के लिए अपने पैरों पर खड़ा होने का भरोसा दिलाती हों, मगर भविष्य में सिर्फ इसी के बूते तरक्की का सपना देखना बेमानी होगा।

पिछले वर्ष लेबर ब्यूरो सर्वे की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 8.7 प्रतिशत ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। जबकि उद्योगों की नजर में कोर्स कर निकलने वाले महज 25 प्रतिशत युवा ही रोजगार देने के काबिल हैं। यदि स्थिति तब है जब देश की एक बड़ी आबादी (करीब 60 करोड़) युवा है। क्षमता होने के बावजूद प्रोफेशनल्स का हुनर निखर कर सामने नहीं आ पा रहा है। अक्सर छात्रों की यही राय होती है कि ग्रेजुएशन के बाद अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती, जबकि वास्तविकता तो यह है कि यदि छात्र ने गंभीरतापूर्वक ग्रेजुएशन की है और उसमें काबिलियत है तो उन्हें रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। देश में सरकारी व निजी क्षेत्र की कई सेक्टर और इंडस्ट्री ऐसी हैं जो बम्पर पैमाने पर ग्रेजुएट को जॉब दे रही हैं। यहां तक कि जॉब करते हुए भी प्रोफेशनल्स इनके बारे में सोच सकता है। एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर एचआर हेड काम करने वाले सुमित अवस्थी का मानना है कि ग्रेजुएशन डिग्री लेकर जब कोई छात्र नौकरी तलाशता है या इस चक्कर में दूसरे शहर जाता है तो शुरू-शुरू में उसे कुछ परेशानी जरूर आती है, लेकिन यदि उसमें हौसला है तो वह ज्यादा दिन तक बेरोजगार नहीं रहेगा।

पिछले वर्ष लेबर ब्यूरो सर्वे की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 8.7 प्रतिशत ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। जबकि उद्योगों की नजर में कोर्स कर निकलने वाले महज 25 प्रतिशत युवा ही रोजगार देने के काबिल हैं। यदि स्थिति तब है जब देश की एक बड़ी आबादी (करीब 60 करोड़) युवा है। क्षमता होने के बावजूद प्रोफेशनल्स का हुनर निखर कर सामने नहीं आ पा रहा है।

कुछ कोशिशें अपनी भी

ग्रेजुएशन के बाद नौकरी आसानी से मिल जाए या नौकरी के दौरान मोहभंग न हो, इसके लिए जरूरी है कि अपने स्तर से कोई चूक न करें। कोर्स के बाद अपने लिए नौकरी चुनते समय यह अच्छी तरीके से देख लें कि क्या जीवन में आपने अपने लिए जो लक्ष्य तय किया है उस फॉर्मेट पर वह नौकरी है या नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय की मनोविज्ञान विभाग की सीनियर फैकल्टी प्रो. अशुम गुप्ता का मानना है कि आज की युवा पीढ़ी तो काफी जागरूक है। उसे अपने लिए अच्छा-बुरा सोचने की पर्याप्त क्षमता है। सोचने वाली बात यह है कि जिस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं, उसके लिए आप कितने योग्य हैं? उस नौकरी के लिए जो-जो स्किल्स चाहिए, क्या आपके अंदर वो सब है। क्योंकि करियर की गाड़ी आपकी पसंद नहीं, बल्कि आपके स्किल्स से चलती है। यदि आप नौकरी के संबंध में पूरी तैयारी के साथ आते हैं तो काम के दौरान न सिर्फ आपको आनंद आएगा, बल्कि आगे बढ़ने के अवसर मौजूद रहेंगे।

इंटर्नशिप को हल्के में न लें

अक्सर छात्र इंटर्नशिप को महज एक सर्टिफिकेट तक सीमित मानते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि यदि बतौर ट्रेनी छात्र इसे गंभीरता से लें तो उनके जॉब मिलने की कोशिश को ये काफी हद तक आसान बना देते हैं।

इंटर्नशिप का मौका मिलने पर नियमित रूप से उपस्थित रहें। हर एक काम को बारीकी से देखें और सीखने का प्रयास करें। यही आगे चलकर आपको एक अच्छे प्रोफेशनल्स के रूप में स्थापित करेगा। सीखने के दौरान आपको जहां भी दिक्कत हो, तत्काल किसी सीनियर से पूछ लें, क्योंकि आप जिस संस्थान में इंटर्नशिप के लिए गए होंगे, वहां हर कदम पर ऐसे लोग मिलेंगे, जो अपने काम में दक्ष होंगे। उनके अनुभव का आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं।

नेटवर्किंग से पहुंचे मंजिल तक

करियर काउंसलर जितिन चावला के अनुसार नेटवर्किंग के सहारे जॉब मिलने की राह काफी आसान हो जाती है। यह नेटवर्किंग कई रूपों में बनती है। पढ़ाई के दौरान सीनियर से तालमेल बढ़िया हो, विजिटिंग फैकल्टी से बराबर संपर्क में रहें और इंटर्नशिप के दौरान वहां के लोगों के नाम और ईमेल आईडी लेकर आप अच्छा प्रभाव छोड़ सकते हैं। आजकल तो वॉटसएप और अन्य नेटवर्किंग साइट्स के जरिए दूरियां काफी कम हो गई हैं। इंटर्नशिप के दौरान यदि आपने संस्थान के कुछ वरिष्ठ लोगों को प्रभावित कर लिया तो आपको नौकरी मिलते देर नहीं लगेगी। आपके क्षेत्र के जो भी महारथी हैं उनसे मेल-जोल बढ़ाएं। वे आपकी भरपूर मदद करेंगे।

रिज्यूमे हो दमदार

पहली नौकरी दिलाने में रिज्यूमें का अहम योगदान होता है। यह रिज्यूमे ही होता है, जो नियोक्ता को आपके बारे में सम्पूर्ण जानकारी देता है। कई बार हम इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं, जबकि आज प्रजेंटेशन का जमाना है। जो जितना अच्छा दिखेगा वह उतना ही अधिक पसंद किया जाएगा। चरण-दर-चरण आगे बढ़ते हुए अब बात विजुअल रिज्यूमे की होने लगी है। रिज्यूमे तैयार करते समय आप अपने समस्त अनुभव और योग्यता के विवरण का उल्लेख करें। अपनी खूबियों और नापसंद को भी अपने रिज्यूमे में जगह दें। जो भी तथ्य उसमें डाल रहे हैं उससे पूरी तरह से वाकिफ रहें।

ऑनलाइन में करें लॉगइन

आज ऑनलाइन क्षेत्र में बंपर वैकेंसी हैं। कहीं आप प्रोग्रमिंग लैंग्वेज सीख पद प्रतिष्ठा सहित अच्छा वेतन पाते हैं, तो कहीं वेबसाइट्स से जुड़ सोशल मीडिया मैनेजर जैसे पदों पर पहुंच अपना हुनर दिखाते हैं। ऑनलाइन की दुनिया विशाल है। यहां आप स्ट्रेटेजी प्लानिंग व निर्माण में अपना योगदाान दे सकते सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो कुछ समय पहले लॉन्च किए गए नेशनल जॉब पोर्टल युवाओं के लिए रोजगार की तलाश पूरी कर सकता है। इससे राज्य सरकारें, परीक्षा कराने वाली संस्था, नौकरी के इच्छुक, जॉब बदलने वाले तथा नियोक्ता सभी जुड़ेंगे।

एयरलाइन्स इंडस्ट्री

- तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बन सकता है एविएशन सेक्टर में भारत 2020 तक। युवाओं के लिए लाखों नए जॉब होंगे।

टेलीकॉम सेक्टर

■ 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा टेलीकॉम सेक्टर में 2020 तक विभिन्न पदों के रूप में

फैशन इंडस्ट्री

■ 9.5 प्रतिशत की दर से ग्रोथ कर रहा है इंडियन डिजाइनर वियर मार्केट। 2020 तक इंडस्ट्री होगी 1000 करोड़।

आईटी सेक्टर

■ 03 करोड़ होगी आईटी इंडस्ट्री में 2020 तक कर्मचारियों की संख्या। देश की आईटी इंडस्ट्री होगी 225 बिलियन यूएस डॉलर।

हेल्थकेयर सेक्टर

■ 04 करोड़ को मिल सकता है हेल्थकेयर सेक्टर में प्रोफेशनल्स को रोजगार 2020 तक।

संक्षिप्त समाचार

खरगे 11 अगस्त को कर सकते हैं जांजगीर-चांपा से चुनावी आगाज

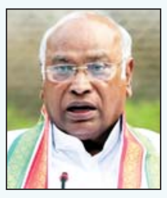

रायपुर। कांग्रेस के विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत जांजगीर-चांपा से हो सकती है। 11 अगस्त को मिनीमाता की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के साथ बैठक में कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे और राहुल गांधी की सभा कराई जाए। इसके बाद यह संकेत मिल रहा है कि खरगे जांजगीर आ सकते हैं। विधानसभा चुनाव की दृष्टि से अविभाजित जांजगीर जिले की छह में सिर्फ दो सीट पर कांग्रेस विधायक हैं। बाकी दो सीट पर भाजपा और दो सीट पर बसपा विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस खरगे से चुनाव प्रचार अभियान की जांजगीर से शुरुआत करके अनुसूचित जाति बहुल विधानसभा क्षेत्र के वोटरों को साधने की फिराक में है। प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए दस विधानसभा सीट आरक्षित है। वर्तमान में सात पर कांग्रेस, दो पर भाजपा और एक सीट पर बसपा के विधायक हैं। कांग्रेस ने एससी वोटरों को साधने के लिए हर ब्लाक में जैतखाम बनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही एससी वर्ग के लिए कई योजनाएं भी शुरू की है। उधर, एससी वोटरों को साधने के लिए भाजपा भी अनुसूचित जाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक छत्तीसगढ़ में करने जा रहा है। इसमें मोर्चा के शीर्ष 80 नेता शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री ने युवाओं के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किए 31 करोड़ से ज्यादा रुपए

रायपुर। सीएम भूपेश बघेल ने आज सोमवार को अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन बेरोजगारी भत्ता योजना की चौथी किश्त बांटी। इस दौरान 1 लाख 22 हजार 625 हितग्राहियों के खाते में 31 करोड़ 71 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किया। बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत अब तक 112 करोड़ रुपये से अधिक की राशि युवाओं खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है। कार्यक्रम में 1 लाख 22 हजार 625 युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के तहत 31.71 करोड़ रूपए की राशि बांटी गई। बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत अब तक 80 करोड़ 72 लाख 30 हजार रुपए की राशि युवाओं के खाते में भेजी जा चुकी है। इस प्रकार जुलाई महीने की राशि शामिल करने पर अब तक 112 करोड़ रुपए की राशि युवाओं के एकाउंट में जा चुकी है। इतना ही नहीं बेरोजगारी भत्ते के आवेदन के साथ ही युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए भी चिन्हांकित किया जा रहा है, जो युवा कौशल प्रशिक्षण चाहते हैं, उन्हें विभिन्न संस्थाओं में प्रशिक्षित किया जा रहा है। 4 हजार 228 युवाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

पार्षद को ऐतराज फिर भी लगेंगे फाल सिलिंग

रायपुर। स्मार्ट सिटी लिमिटेड का एक और स्मार्ट काम सामने आ रहा है जब लिली चौक पुरानीबस्ती के अंदर टूरी हटरी बाजार के सौंदर्यीकरण के लिए स्वीकृत 30 लाख का काम किया जा रहा है। यहां 37 चबूतरे हैं,ऊपर है टीन का शेड और उसके ऊपर घने पेड़ हैं जिसमें पत्तों का जमावड़ा हमेशा बने रहता है। टीन शेड पर फाल सिलिंग किया जा रहा है। पार्षद जितेन्द्र अग्रवाल ने इस पर आपत्ति जतायी है कि यह अनावश्यक है इसलिए कि ज्यादा दिन टिक पाना मुश्किल है। जानकार भी बताते हैं कि कांक्रीट की छत पर ही फाल सिलिंग किया जाता है। केवल पैसे को खर्च में दिखाना है इसलिए अफसर कुछ भी कर रहे हैं।

न्यायमूर्ति तिवारी बने बिलासपुर हाईकोर्ट के स्थाई जज

रायपुर। मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा ने आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कोर्ट हाल नम्बर 1 में आयोजित एक गरिमामय कार्यक्रम में न्यायमूर्ति श्री दीपक कुमार तिवारी को स्थायी जज के रूप में शपथ दिलाई। उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति श्री दीपक कुमार तिवारी की नियुक्ति 08 अक्टूबर 2021 को एडिशनल जज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में हुई थी। विधि एवं विधायी कार्य विभाग, नई दिल्ली द्वारा 28 जुलाई 2023 को न्यायमूर्ति श्री दीपक कुमार तिवारी को स्थायी जज में नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी की गयी थी। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में समस्त न्यायमूर्तिगण रजिस्ट्री व ज्यूडिशियल एकेडमी के न्यायिक अधिकारीगण, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर, प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, रायपुर अधिवक्तागण एवं न्यायमूर्ति श्री दीपक कुमार तिवारी के परिवार के सदस्य उपस्थित थे।

भाजपा अजा मोर्चा की बैठक आज

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक बैठक आगामी 01 अगस्त को राजधानी रायपुर में होने जा रही है। आगामी प्रदेश विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव की रणनीतिक तैयारियों दृष्टि से छत्तीसगढ़ में 23 वर्ष में पहली बार आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में देशभर के 80 दिग्गज अजा नेता हिस्सा लेंगे। भाजपा अजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक नवीन मार्कण्डेय ने बताया कि बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष, राष्ट्रीय संगठक वी. सतीश, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री व मोर्चा प्रभारी सी.टी. रवि, अजा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालसिंह आर्य सहित मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी, 35 संगठन राज्यों के मोर्चा प्रदेश प्रभारी, सहप्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं।

शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक सड़क निर्माण कार्य है प्राथमिकता : बघेल

बारिश के बाद सड़कों की त्वरित गति से करें मरम्मत, सभी निर्माण एजेंसियां आपस में समन्वय बनाकर करें सड़कों का निर्माण

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बारिश खत्म होने के तुरंत बाद सड़कों की मरम्मत करवाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा है कि आम जनता के सुविधा के लिए सड़कों के अधूरे कार्य, सड़कों की मरम्मत और नवीनीकरण के कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में सड़क निर्माण के कार्य मे लगी सभी एजेंसियों को आपस में सामंजस्य बनाकर तेजी से काम करना है।

मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान रायपुर शहर के चार महत्वपूर्ण कार्यों की भी जानकारी ली। इसमें तेलीबांधा में फ्लाईओवर का निर्माण, शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक सड़क निर्माण, अटल एक्सप्रेस वे से वीआईपी रोड़ निर्माण तथा खारून रिवर फंट के निर्माण कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने विशेष तौर पर शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक निर्माण तथा भू -अर्जन प्रकरण समेत लगभग 137 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 510 मीटर लंबी सड़क को लेकर अधिकारियों को निर्देश देते हुए जल्द ही इसका कार्य शुरू कराने की बात कही है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक लेते तेलीबांधा ओवरब्रिज और एक्सप्रेस वे को वीआईपी रोड से जोड़ने वाले ओवरब्रिज के बारे में भी अधिकारियों से समीक्षा की। बैठक में लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, शिक्षा मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, नगरीय प्रशासन विभाग के विशेष सचिव श्री अयाज भाई तंबोली, सीजीआरआईडीसीएल के प्रबंध संचालक श्री सारांश मित्तर एवं लोक निर्माण विभाग के ईएनसी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने समीक्षा करते हुए कहा कि बची हुई सड़कों का निर्माण कार्य जल्दी पूरा होना चाहिए। समीक्षा बैठक में जानकारी देते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरगुजा क्षेत्र में कुल 332.7 किलोमीटर सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें 292.2 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है जबकि 40.5 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य अभी शेष है जिसे बारिश के मौसम के बाद जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इसी प्रकार रायगढ़ क्षेत्र में भी 155.4 किलोमीटर सड़कों का कार्य पूरा किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि शेष कार्य भी जल्द पूरा किया जाए।

मुख्यमंत्री से छत्तीसगढ़ी भाषा छात्र विकास समिति के सदस्यों ने की सौजन्य मुलाकात

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज यहाँ उनके निवास कार्यालय में संसदीय सचिव श्री कुंवर सिंह निषाद के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ी भाषा छात्र विकास समिति (एम. ए. छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन) के सदस्यों ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री का छत्तीसगढ़ी भाषा के छात्रों के लिए प्राध्यापक पद पर भर्ती किये जाने की घोषणा के लिए प्रतीक चिन्ह, गमछा, शॉल एवं श्रीफल भेंटकर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर एम. ए. छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन के अध्यक्ष श्री ऋतुराज साहू, श्रीमती अंजनी चन्द्रवंशी, श्री संजीव साहू एवं सदस्यगण उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान छत्तीसगढ़ी साहित्यकार श्री दुर्गा प्रसाद पारकर की रचनाओं के संग्रह पर आधारित गीत-संग्रह सुमिरँव छत्तीसगढ़ का भी विमोचन किया। श्री पारकर ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस गीत संग्रह के गीतों को पद्मश्री महेंद्र कपूर, ममता चन्द्राकर जैसे दिग्गज कलाकारों ने भी अपनी आवाज दी है। उनकी रचनाएँ बहु हाथ के पानी और सुदामा के चाउर हेमचंद विश्वविद्यालय दुर्ग और रविशंकर विश्वविद्यालय के एमए छत्तीसगढ़ी के पाठ्यक्रमों में शामिल है। मुख्यमंत्री ने उन्हें इस गीत संग्रह के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री बघेल से रायपुर संभाग के युवाओं के साथ भेंट मुलाकात के दौरान एम. ए. छत्तीसगढ़ी विषय में स्नातकोत्तर श्रीमती अंजनी चंद्रवंशी ने छत्तीसगढ़ी भाषा के प्राध्यापक हेतु भर्ती लिये जाने की मांग की थी जिस पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ी भाषा के प्राध्यापक के लिए भर्ती की घोषणा की थी।

अफसर ने महिला संविदा कर्मचारी को दी धमकी, एफआईआर दर्ज

रायपुर। राजधानी रायपुर में संयुक्त संचालक पर अपने अधीनस्थ महिला संविदा कर्मचारी से अभद्रता व्यवहार करने का आरोप लगा है। युवती ने अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अफसर ने सबके सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहने की बात कही है। पूरा मामला पंडरी थाने क्षेत्र का है। संविदा कर्मचारी युवती ने पशु चिकित्सा सेवाएं पंडरी में पदस्थ संयुक्त संचालक डॉ. शंकर लाल उइके के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आरोपी संयुक्त संचालक के खिलाफ पुलिस ने धारा 294 और 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज किया है।

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, पशु चिकित्सा सेवाएं पंडरी में पदस्थ संविदा कर्मचारी युवती को संयुक्त संचालक ने अपने चेंबर में बुलाकर अभद्रता से बात की। घटना के समय चेंबर में 3 और लोग भी मौजूद थे। इसमें से 1 महिला स्टाफ भी थी। युवती ने उन तीन लोगों पर मौन रहने का आरोप लगाया है।

युवती ने रिपोर्ट में कहा कि संयुक्त संचालक ने अभद्र बातें कहीं। इसके साथ ही करियर बर्बाद करने की धमकी भी दी। कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी की बात भी कही। इतना ही नहीं अनुसूचित जनजाति विभाग में फंसा देने की धमकी भी दी है। उइके ने वहां मौजूद रजिस्टर को फेंका और संविदा युवती की मोबाइल छिनकर महिला स्टॉफ को जांच करने के लिए कहा।

कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र रायपुर के तहत आने वाले उपकेन्द्र तेलीबांधा में एवीएफओ संविदा पद पर एक युवती पदस्थ है। युवती की रिपोर्ट के मुताबिक 25 जुलाई को लगभग 11 बजे जेडी कार्यालय रायपुर ग्रुप में मैसेज आया था। जिसमें एक मोबाइल फोन से युवती को कॉल आया। इस दौरान युवती के कॉल नहीं उठाने की शिकायत मिली। इसके बाद उसे 12 बजे तेलीबांधा के एवीएफओ को रजिस्टर के साथ मिलने को कहा था। तब प्रार्थिया ने संयुक्त संचालक के पशु चिकित्सा सेवाएं पंडरी रायपुर में 12 बजे पहुंची। इस दौरान अधिकारी ने युवती से अभद्र व्यवहार किया।

इस मामले में पशु चिकित्सा सेवाएं पंडरी में पदस्थ संयुक्त संचालक डॉ. शंकर लाल उइके ने कहा कि ये सभी आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं। स्वइक करवाने वाली युवती के खिलाफ कई शिकायतें आई थी। इसलिए उसे बुलाया गया था। जिस चेंबर में उसे बुलाया गया था वहां और भी स्टाफ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बाकी लोग भी थाना जाकर अपना बयान दर्ज करा लिए हैं। जब मुझे बुलाया जाएगा तो मैं भी अपना बयान दर्ज कराऊंगा।

जुडॉ आज शुरू करेंगे हड़ताल

रायपुर। जूनियर चिकित्सकों ने स्टाइपेंड की अपनी वर्षों पुरानी मांग पर अब आर-पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। जूनियर डॉक्टर जहां 01 अगस्त से ओपीडी में सेवा बंद कर देंगे तो वहीं 02 अगस्त से आपातसेवा में भी अपनी भागीदारी हटा लेंगे। इस संबंध में जुडा द्वारा सभी विभागाध्यक्षों को सूचित कर दिया गया है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन इस बात से खासे नाराज हैं कि राज्य सरकार द्वारा कई तरह के आश्वासन दिए जाने के बाद भी आज तक उनकी मांगों पर कभी भी गंभीरता से विचार नहीं किया गया। ज्ञात हो कि जनवरी माह में भी जुडा ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल किया था। लेकिन इसके बाद भी उनके पक्ष में किसी तरह का कदम नहीं उठाया गया। जूनियर चिकित्सकों की हड़ताल से अस्पताल में जहां उपचार व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है तो वहीं मरीजों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

छत्तीसगढ़ सरकार की पहल से एसटी में शामिल हुई 12 जातियां

रायपुर। प्रदेश की 12 जातियों को जनजातियों की सूची में शामिल करने को लेकर एक बार फिर श्रेय की सियासत शुरू हो गई है। भाजपा प्रदेश नेतृत्व ने अपनी पहल का दावा किया, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा था, जिसके बाद यह सफलता हासिल हुई है।

पूर्ववर्ती रमन सरकार को पहल पर तंज कसते हुए सीएम बघेल ने कहा कि डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन रमन सिंह को चलती नहीं थी। भाजपा के द्वारा पत्र लिखा गया था, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। हमने प्रयास किया तब जाकर सफलता मिली है।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव बोल रहे हैं कि 10 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। वहीं, केंद्रीय मंत्री 72,000 लोगों को लाभ मिलने की बात कह रहे हैं। भाजपा केवल लाभ लेने का काम कर रही है, लेकिन हमने कई पत्र लिखे। मुख्यमंत्री बघेल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि यूपीए सरकार ने वर्ष 2008 में गारंटी दी थी, जिसमें पांच योजनाएं थी। इन गारंटियों के केंद्रांश को मोदी सरकार घटा रही है। पहले ही योजना में केंद्र की राशि ज्यादा थी, जिसे धीरे-धीरे कम करने का काम किया गया। गरीबों के आवास को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अप्रैल से हमने आर्थिक सर्वेक्षण कराया है, जिसमें सबको लाभ मिलेगा।

चारा घोटाला से भी बड़ा है गोबर घोटाला, भूपेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट की दुर्गति : चंदेल

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सोमवार को एक प्रेसवार्ता कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा। नारायण चंदेल ने कहा कि भूपेश सरकार घोटालों सरकार है। बघेल सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में ही करोड़ों का घोटाला हुआ है।

नारायण चंदेल ने राज्य सरकार पर 269 करोड़ों रुपये के गोबर घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने इस घोटाले को बिहार के चारा घोटाले से बड़ा बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को कायदे से इसकी सीबीआई जांच कराने की सिफारिश केंद्र से करनी चाहिए। चंदेल ने अपनी बातों को विस्तार से बताते हुए कहा कि गाय, गोबर, गौठान, नरवा और घुरवा, प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट हैं। इस ड्रीम प्रोजेक्ट की राज्य में जैसी दुर्गति हुई है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रदेश सरकार की बाकी योजनाओं और कार्यों का क्या हुआ होगा।

नेताप्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों प्रदेश स्तर पर संगठन के जरिए 948 गौठानों का निरीक्षण कराया था। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई जगह गौठानों पर ताले लगे थे। अनेक स्थानों पर गौ माता के लिए न तो पैरा का इंतजाम था और न ही पानी का। यहां गायों की देखरेख करने के लिए कोई व्यक्ति भी तैनात नहीं था।

वहीं, मंत्री अमरजीत भगत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन उसमें विफल रहे। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार लगातार युवाओं को रोजगार दे रही है और बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता भी शुरू किया है। इतना सब करने के बाद भी कुछ न करने वाली भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही है।

इसके बाद मंत्री भगत ने चुटकी लेते हुए कहा कि चंदेल अच्छे व्यक्ति हैं, पर उन्हें जितना सिखाया जाता है उतना ही बोल पाते हैं। साथ ही रमन सिंह के चेहरे पर भाजपा के चुनाव लड़ने से जुड़े प्रश्न पर भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की नाव डूब गई है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ के विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। कांग्रेस सरकार यहां की लोकसंस्कृति तीज-त्योहार को बढ़ावा दे रही है। जनता का साथ कांग्रेस को ही मिलेगा।

भाजपा अजा मोर्चा की बैठक आज

छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति

रायपुर। छत्तीसगढ़ भाजपा पूरी तरह से चुनावी मोड में है। इस क्रम में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की कल मंगलवार को बैठक होगी। इसमें शामिल होने के लिए बीजेपी संगठन के नेताओं का रायपुर में जमावड़ा लग रहा है। बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता रायपुर आएंगे। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालसिंह आर्य 31 जुलाई को रात 8 बजे राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। वहीं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय संगठक वी सतीश, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री और मोर्चा प्रभारी सीटी रवि 1 अगस्त की सुबह में रायपुर आएंगे।

इसके अलावा इस बैठक में मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी, 35 संगठन राज्यों के मोर्चा प्रदेश प्रभारी, सहप्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष भी शिरकत करेंगे। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नवीन मार्कण्डेय ने बताया कि बैठक में संगठनात्मक विषयों के साथ ही महासंपर्क अभियान की रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से पिछले 9 वर्षों के शासनकाल में अजा वर्ग के कल्याण की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसमें सामाजिक न्याय और राजनीतिक सहभागिता की दिशा में क्रांतिकारी पहल हुई है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से शुरू हुए कल्याणकारी कार्यक्रमों और योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने की योजना पर बैठक में चर्चा की जाएगी। साथ ही छत्तीसगढ़ और राजस्थान में दलितों, विशेषकर दलित महिलाओं पर बढ़ी अत्याचार की घटनाओं को लेकर दोनों प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनमत जागृत करने की योजना बनाई जाएगी।

कृषि में पारंपरिक ज्ञान से ही संभव है जलवायु परिवर्तन का सामना: मंडावी

- निक्रा परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश के कृषि विज्ञान केन्द्रों की दो दिवसीय कार्यशाला

रायपुर। छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश के जिले में जलवायु सहनशील कृषि हेतु नवाचार (निक्रा) परियोजना संचालित करने वाले 11 कृषि विज्ञान केन्द्रों की दो दिवसीय वार्षिक समीक्षा कार्यशाला का आयोजन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के निदेशालय विस्तार सेवाएं में किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन श्री मोहन मण्डावी, सदस्य, कृषि संसदीय समिति, भारत सरकार एवं सांसद, कांकेर के मुख्य आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. व्ही.के. सिंह, निदेशक, केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद ने की।

कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री मोहन मण्डावी ने इस अवसर पर जैविक खेती को बढ़ावा देने एवं रसायनों के उपयोग को कम करने हेतु जोर दिया, साथ ही कृषि के क्षेत्र में पारंपरिक ज्ञान का उपयोग अधिक से अधिक करने की आवश्यकता बतलाई। श्री मण्डावी ने कहा कि पहले कृषक अपने पारंपरिक ज्ञान के आधार पर मौसम आधारित खेती करते थे, जिससे सभी कार्य समय पर एवं मौसम की प्रतिकूलता से बचाव के साथ होता था। उन्होंने कृषि एवं संबंधित विषयों पर स्थानीय भाषा में कृषकों को सलाह देने हेतु वैज्ञानिकों को निर्देशित किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉ. व्ही.के. सिंह ने अपने उद्बोधन में मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के निक्रा परियोजनान्तर्गत अंगीकृत ग्रामों में चल रही गतिविधियों तथा बदलते जलवायु, बढ़ते तापमान एवं अनियमित वर्षा के कारण फसलोत्पादन में कमी, पालतू पशुओं की उत्पादकता में कमी तथा जलवायु परिवर्तन के अन्य दुष्प्रभावों से निपटने की रणनीति की जानकारी दी। अटारी, जबलपुर के निदेशक डॉ. एस.आर.के. सिंह द्वारा निकरा परियोजना की शुरूआत एवं इसके लाभकारी परिणामों के बारे में जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ राज्य में इस परियोजना के अन्तर्गत 3 कृषि विज्ञान केन्द्र दन्तेवाड़ा, भाटापारा एवं बिलासपुर को चिन्हित किये गये हैं। उन्होंने जलवायु सहनशील वैज्ञानिक तकनीकों के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया। डॉ. जे.व्ही.एन.एस. प्रसाद ने निकरा परियोजना के सभी अनुशंसित अवयवों में से जिले की जलवायु के अनुरूप तकनीक का चयन कर कृषकों के खेतों में प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण आयोजित करने का आग्रह किया। वर्षा आधारित खेती में दोफसली रकबा बढ़ाने हेतु उतेरा, जीरो टिलेज कृषि को प्रसारित करने का सुझाव दिया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के निदेशक विस्तार डॉ. अजय वर्मा ने समय-समय पर एवं कम लागत में कृषि कार्य सम्पन्न करने हेतु मौसम आधारित कृषि यंत्रीकरण का समुचित उपयोग करने हेतु सुझाव दिये तथा बदलते मौसम के अनुरूप कृषि की तकनीकी का प्रसार करने का आग्रह किया।

डॉ. विजय जैन, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र, पाहन्दा, दुर्ग ने दुर्ग जिले में निकरा परियोजनान्तर्गत जिले में किये गये विभिन्न कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। मध्यप्रदेश के कृषि विज्ञान केन्द्र दतिया, झाबुआ, टीकमगढ़, भिण्ड, डिण्डोरी, रतलाम, मुरैना एवं छतरपुर तथा छत्तीसगढ़ के कृषि विज्ञान केन्द्र दुर्ग, महासमुन्द एवं रायगढ़ के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुखों तथा नोडल अधिकारी ने विगत वर्षों के कार्यों तथा आगामी कार्ययोजना की प्रस्तुतिकरण दिये, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा आवश्यकतानुसार सुझाव एवं निर्देश दिये गये। इस अवसर पर डॉ. व्ही.के. पाण्डे, अधिष्ठाता, कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, रायपुर, डॉ. जी.के. दास, अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, रायपुर, डॉ. रेड्डी, प्रमुख वैज्ञानिक, डॉ. जी.पी. अयाम, डॉ. डी.पी. पटेल, डॉ. ज्योति भट्ट एवं निकरा कृषि विज्ञान केन्द्रों के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, नोडल अधिकारी, वैज्ञानिक एवं अंगीकृत गांव के कृषक प्रतिनिधि उपस्थित थे।

500 से अधिक लोगों ने किया भाजपा प्रवेश

- मांढर में अरुण साव ने सुना मन की बात
- छत्तीसगढ़ में चल रही झूठ फरेब की सरकार, जनता देगी जवाब- अरुण साव
- आज़ाद भारत के इतिहास में गोबर में भी घोटाला कर कीर्तिमान रचने वाली सरकार है कांग्रेस की भूपेश सरकार

रायपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव मांढर में आयोजित भाजपा प्रवेश कार्यक्रम में शामिल हुए। धरसींवा विधानसभा के 500 लोगों को भाजपा प्रवेश कराने के बाद साव ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। साव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार को झूठ फरेब वाली सरकार बताया है।

साव ने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ में झूठ फरेब वाली सरकार चल रही है। यहां के मुख्यमंत्री इतना अधिक झूठ बोलते हैं कि गधे को भी ज्वर आ जाये। जब हम सुबह उठकर राम राम कहते हैं उस समय यहां के मुख्यमंत्री झूठ बोलने के लिए निकलते हैं।

वाह भूपेश बघेल जी हम छत्तीसगढ़ के गांव में रहने वाले लोग हैं। आप छत्तीसगढ़िया लोगों को बासी खाना सिखा रहे जैसे बासी की उत्पत्ति तो आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद ही हुई है। आपके मुख्यमंत्री बनने से पहले छत्तीसगढ़ के लोग बासी खाना नहीं जानते थे। छत्तीसगढ़िया लोग हरेली तिहार और गेड़ी चढ़ना नहीं जानते थे। ऐसा प्रचारित करने का काम छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने किया है।

काम के नाम पर किया केवल भ्रष्टाचार

मुख्यमंत्री भूपेश काम के नाम पर छत्तीसगढ़ को चारों तरफ से केवल लूटने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को भूपेश बघेल ने पूरे देश में बदनाम कर दिया है। कोयला घोटाला, शराब घोटाला, चावल घोटाला, जमीन घोटाला, छ्रस्स्न घोटाला, गौठान घोटाला इस घोटालेबाज सरकार ने तो गोबर में भी घोटाला करने का काम कर दिखाया है।

साव ने रोका छेका अभियान को असफल बताया उन्होंने कहा कि यह रोका छेका की बात करती है। जिसके लिए गौठान बनाये हैं। आज गौठान सुनसान पड़े हैं। सड़कों पर गाय बैल बैठे हुए हैं। सड़क गौठान बन गया है। सड़कों पर गायों की मौत हो रही है। लेकिन ये सरकार गाय और गोबर के नाम पर भी भ्रष्टाचार करने से पीछे नहीं हटी।

प्रदेश में विकास कार्य ठप

अरुण साव ने मुख्यमंत्री भूपेश के पौने पांच साल के कार्य को लेकर कहा कि इस कांग्रेस की सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। प्रदेश में विकास कार्य पूर्ण रूप से ठप्प पड़ गया है। एक रुपये का विकास कार्य इस सरकार ने नहीं किया है और इनके घोषणा वीर मुख्यमंत्री रोज घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं।

युवती की हत्या पर छत्तीसगढ़ सरकार मौन

साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो चुकी है। हत्या, लूट, दुष्कर्म की घटनाएं प्रतिदिन ही रही है। लेकिन यहां के मुख्यमंत्री चेहरा चमकाने में लगे हैं। साव ने कहा कि इसी धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में एक युवती की लाश ग्राम टेकारी गौठान के पास मिली। ग्राम सांकरा में विधायक के कार्यालय के पास 8 साल के बच्ची का दुष्कर्म हो गया लेकिन यहां के क्षेत्रीय विधायक मौन है, कांग्रेस की सरकार मौन है। आज छत्तीसगढ़ की बेटियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं। जिसके लिए जिम्मेदार ये कांग्रेस की सरकार है।

छत्तीसगढ़ की जनता देगी जवाब

साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ को लूटने वाले और छत्तीसगढ़िया लोगों को ठगने वाले इस कांग्रेस सरकार को प्रदेश की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में उखाड़ कर फेंकेगी। छत्तीसगढ़ के लोग बहुत भोले हैं। कांग्रेस के झूठे वादों और फरेब में जनता नहीं आने वाली। इस पौने पांच साल में छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री का ओ स्वरूप देख लिया है। जो अब यहां की जनता दुबारा देखना नही चाहेगी।

मेरी बात

✍ गिरीश पंकज

पत्थरबाजी की मानसिकता

यह आज का सिलसिला नहीं है ।पुराना सिलसिला है। हिंदुओंकी धार्मिक यात्राओं पर कुछ सिरफिरे लोगों द्वारा पत्थरबाजी की जाती है।छत्तीसगढ़ में समरसता का वातावरण है। यहां इस तरह की अराजकता नहीं दिखती। लेकिन अन्य कुछ प्रांतों में बीच बीच मे पत्थरबाजी की घटनाएँ ज़रूर होती हैं। जैसे अभी एक जगह कावंड़ियोन पर पथराव किया गया तो 31 जुलाई को मेवात के नूंह कस्बे में बृज मंडल धार्मिक यात्रा के दौरान पथराव बाजी हुई। स्वाभाविक है कि यात्रा में शामिल लोगों ने भी जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने ने भी पत्थर फेंके और हिंसक स्थिति निर्मित हो गई। अब वहां धारा 144 लागू कर दी गई है। इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। प्रशासन ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे अफवाहों से बचें। प्रशासन यही कर सकता

है लेकिन अंततः शांति व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व समाज का है। खासकर उस समाज का, जिस समाज के कुछ भटके लोगों को सौहार्द बिगाड़ने का बड़ा शौक होता है। न जाने उनके भीतर ऐसी कौन सी धार्मिक कट्टरता उफान मारती है कि किसी धार्मिक यात्रा का स्वागत करने के बजाए, ये लोग उस पर पत्थर बरसाने लगते हैं। जबकि इसी समाज मे अनेक सुलझे लोग भी हैं, जो धार्मिक जुलूसों पर फूल बरसाते हैं। होना यही चाहिए। हम ऐसा समाज चाहते हैं, जहॉ हिन्दू मुस्लिम एक दूसरे के जुलूसों पर फूल बरसाएं। उनका तहे दिल से स्वागत करें। कभी कभार ऐसा होता भी है।ऐसा वे ही करते हैं, जो कुछ पढ़े लिखे हैं। जो समझते हैं कि मिलजुल कर, भाईचारे की भावना के साथ रहना चाहिए। लेकिन जो केवल मूर्ख हैं, अराजक हैं, गुंडे हैं, वे अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आते। पथराव करने लगते हैं। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि कोई भी धार्मिक यात्रा निकले तो वहाँ पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात रहे। वह विघ्नसंतोषी लोगों से सख्ती के साथ निबटे। मेवात में पुलिस ऐसा कुछ नहीं कर सकी, यह दुख की बात। लेकिन पुलिस भी कितना देखे, जब हिंसक पागल भीड़ अपने पर उतारू हो जाए तो उनको सँभालना कठिन हो जाता है। समाज में कुछ लोग अभी भी उग्र धार्मिक कट्टरता के शिकार हैं। इनके जीवन मे उनके धर्म की श्रेष्ठ बातों का कोई असर नहीं दिखता। मोहब्बत की बातें तो करते हैं, मगर व्यवहार में वह दिखता नहीं। दरअसल सारी गलती उनके धर्मगुरुओं का भी है, जो अपने धर्म के नए बच्चों को समझाते नहीं है। ऊपर वाला कभी भी पथराव से खुश नहीं होगा। ऐसे लोग इस भ्रम में न रहें कि ऐसा करके वे ज़न्नत चले जाएंगे। समाज मे हिंसा फैलाने वाले दोज़ख यानी नरक में ही जाने वाले हैं। इसलिए ऐसा काम ही क्यों करें। प्यार, मोहब्बत, भाईचारे के साथ रहें। ऐसी शिक्षा देने का काम मौलानाओं का है, अन्य धर्मगुरुओं का है। यह बहुत आवश्यक है कि हर बच्चे को बचपन से ही यह समझाया जाए कि तुमको अपने धर्म के अलावा दूसरे के धर्म का सम्मान करो। हम दूसरे के धर्म की इज़्ज़त करेंगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा। नफरत से नफरत ही बढ़ेगी। एक उधर से पत्थर चलेंगे, तो इधर से भी पत्थर चलेंगे। नुकसान होगा समाज का। अशांति फैलेगी। बेकसूर लोग प्रभावित होंगे। सभ्य समाज में हिंसा, अलगाव की कोई जगह न रहे। लेकिन व्यवहार में यह कल्पना साकार नहीं हो पाती। नैतिक शिक्षा का अभाव बड़ा कारण है। हम कहते वसुधैव कुटुम्बकम मगर कोई इसे ही नहीं माने तो क्या किया जा सकता है। फिर भी उन्मादग्रस्त धार्मिको (?) को निरन्तर समझाया जाए कि पत्थरबाज़ी से कोई धार्मिक लाभ नहीं होने वाला। यह काम उनके धर्मगुरु ही कर सकते हैं। अगर वे सच्चे धर्मगुरु हैं तो!!

प्रधानमंत्री आवास योजना का इंदिरा आवास से कोई तुलना नहीं : कौशिक

- पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री के बयान पर किया पलटवार

रायपुर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस जब इंदिरा आवास दे रही थी उसमें केवल 10 हजार रू मात्र ही दिया जाता था, वह भी गांव के मात्र 2 या 3 परिवारों को ही मिलता था। अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2024 तक देश के हर व्यक्ति के सर पर छत हो इसी लक्ष्य निर्धारित करके प्रधानमंत्री आवास योजना को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और देश के प्रत्येक परिवार को इस योजना का लाभ मिले इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं किन्तु प्रदेश की कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ की जनता से उनका यह हक व अधिकार छीन रही है और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री आवास योजना की तुलना इंदिरा आवास से करके अपने कमजोरियों व नाकामियों पर पर्दा डाल रहे हैं। उन्होनें कहा कि कांग्रेस की सरकार प्रधानमंत्री आवास तो बना नहीं पा रही है, मैचिंग ग्रांड की राशि भी नहीं दे पा रही है यही कारण है कि कांग्रेसी अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए केवल केन्द्र सरकार पर आरोप लगाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में यह

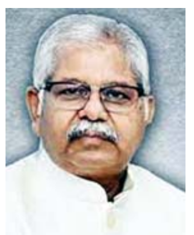

साबित हो चुका है कि 12 लाख परिवारों को कांग्रेस की इस सरकार ने प्रधानमंत्री आवास से वंचित रखा है और उनके सर से छत छीनने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने जो सर्वे कराया है जिसकी लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता के सामने स्पष्ट करें कि उनके प्रथम सर्वे में कुल कितने लोग पात्र सूची में है और कितने अपात्र सूची में है, तथा उनके द्वारा कराई गयी सक्रुटनी के पश्चात कितने लोगो का नाम पात्र सूची में आए है और कितने लोग अपात्र हो गए है? इससे स्पष्ट हो जायेगा की प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार कितनी गंभीर है।

हार मान चुके भूपेश अब हिंसा के सहारेः केदार

रायपुर।भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नसीहत दी है कि वे प्रदेश के मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने सवाल किया कि क्या बघेल भी अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को नाकारा समझते हैं और मानते हैं कि सारे अक्षम लोग कांग्रेस में भरे हैं? अगर वे ऐसा नहीं सोचते तो उन्हें वह काम करना चाहिये जिसके लिये जनता ने उन्हें नियुक्त किया है। और राष्ट्रीय मुद्दों पर राष्ट्रीय नेताओं को बोलने दें। मणिपुर हिंसा पर बघेल द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ बेजा बयानबाजी पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए श्री कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दायित्व को भलीभाँति समझते हैं। मुख्यमंत्री बघेल को पद की गरिमा व मर्यादा का ध्यान रखना चाहिये।

भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री कश्यप ने कहा कि प्रदेश में अभी हाल ही खल्लारी विधानसभा क्षेत्र के एक किसान कन्हैया सिन्हा ने विवश होकर आत्महत्या कर ली, छत्तीसगढ़ महतारी के हताश-निराश युवा पुत्र पूर्ण नग्न होकर प्रदर्शन करने के लिए विवश हुए, आदिवासी बहुल बस्तर के दोरनापाल में तीन साल की बच्ची और सुकमा जिले के एर्राबोर थाना के पोटा केबिन स्थित आदिवासी बालिका छात्रावास में पहला कक्षा की पाँच वर्षीया छात्रा के साथ हैवानियत और दरिंदगी इंतेहा करके दुष्कर्म किया गया, कर्मचारियों के नियमितीकरण के मुद्दे पर प्रदेश सरकार की वादाख़िलाफ़ी के विरोध में लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, एक संविदा कर्मचारी आंदोलन के दौरान अपनी जान बलिदान कर देता है, घोटालों-भ्रष्टाचार के जरिए युवाओं के रोज़गार के अवसर छिन गए। बस्तर के ही कोण्डागाँव जिले के ग्राम बड़गई में मानवता को शर्मसार करने वाले एक मामले में शादीशुदा युवक और उसकी प्रेमिका को निर्वस्त्र करके सरेआम घुमाया गया।

प्रियंका बिस्सा व्यास को राजनीति विज्ञान में डॉक्टरेट डिग्री अवार्ड

रायपुर। पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ की बेटी डॉ प्रियंका बिस्सा व्यास को युवाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को उत्पन्न करने में सोशल मीडिया की भूमिका- एक विश्लेषणात्मक मूल्यांकन विषेयक शोध कार्य हेतु डॉक्टरेट डिग्री अवार्ड की गयी । यह शोध कार्य शोध निर्देशक प्रोफ. डॉ. सुभाष चंद्राकर दुर्गा महाविद्यालय के मार्गदर्शन में पूर्ण हुआ। राष्ट्पति सम्मानित डॉ. प्रियंका बिस्सा ने सोशल मीडिया के माध्यम से युवा राजनीतिक सशक्तिकरण के मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पहलुओं का व्यापक विश्लेषण किया है। यह अभूतपूर्व अध्ययन भारत में अपनी तरह का पहला अध्ययन है। वर्तमान भारतीय राजनीति में सोशल मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ऐसे में यह शोध बहुत प्रासंगिक हो गया हैं।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

भूपेश सरकार ने बनाया 13 लाख से अधिक आवासः बैज

रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा गरीबों को आवास उपलब्ध करवाने की योजना इंदिरा आवास का ही बदला नाम है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने इंदिरा आवास योजना में शुरूआत में केंद्रांश 80 और

राज्यांश 20 था जो बाद में 75 और 25 हुआ, मोदी राज में यह 60 और 40 हो गया राज्यों की भागीदारी बढ़ा दी गयी। केंद्र सरकार अपना हिस्सा न देने पड़े इसलिये प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति में हमेशा कोताही बरतती है। गरीबों के आशियाने के सपने को चकनाचूर करने वाले गरीबों के हितैषी बनने का पाखंड कर रहे हैं। भाजपा छत्तीसगढ़ में राज्य शासन पर झूठा आरोप लगाकर प्रधानमंत्री आवास पर भ्रम फैलाती है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार इस दिशा में सतत प्रयासरत रहती है कि प्रत्येक जन कल्याणकारी योजना का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिले, चाहे वह केंद्र की योजना हो अथवा राज्य की। राज्य में वर्तमान में कांग्रेस सरकार बनने के बाद प्रदेश में कुल शहरी और ग्रामीण मिलाकर कांग्रेस सरकार बनने के बाद 1,304,000 आवास स्वीकृत हुये है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में 2 लाख 69 हजार मकान स्वीकृत हुये। प्रधानमंत्री आवास के शहरी क्षेत्र का ही यदि तुलनात्मक अध्ययन करे तो रमन सिंह सरकार ने 4 साल में शहरी क्षेत्र में मात्र 19,000 मकान बनाये थे तथा भूपेश सरकार ने 4 साल में 247,000 मकान बनाये है।

रमन सरकार की रेपिस्ट बचाओ मुहिम का पर्दाफाश हुआः ठाकुर

रायपुर। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बयान पर तीखा पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार में कानून का राज है। बलात्कारी कोई भी हो चाहे वो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का पुत्र हो जिस पर आदिवासी बेटी से दुराचार के आरोप लगे,

चाहे पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह का ओएसडी ओपी गुप्ता हो जिस पर नाबालिग ने दुष्कर्म के आरोप लगाये तो चार साल तक रमन सरकार ने पीड़िता का एफआईआर दर्ज नही होने दिया था। रमन सरकार ने रेपिस्ट को बचाया था। भूपेश सरकार में उक्त पीड़िता को न्याय मिला रेपिस्ट पर कार्यवाही हुई और रमन सरकार की रेपिस्ट बचाओ मुहिम का पर्दाफाश हुआ। भाजपा नेताओं का संस्कार बलात्कारी अपराधी के पक्ष में खड़ा होने का है पूरा देश ने देखा है किस प्रकार से उन्नाव कठुवा में हुई रेप की घटना में शामिल भाजपा नेताओं को बचाने के लिए भाजपा के नेता झंडा लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। रेपिस्ट भाजपा नेता कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद के पक्ष में पूरी भाजपा खड़ी थी अभी जंतर मंतर में भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवान बेटियां महीनों तक अनशन की लेकिन भाजपा हमेशा की तरह ही उस आरोपी सांसद के साथ खड़ी रही और बेटियों को ही भला बुरा कहने लगे। झारखंड में भाजपा शासन के दौरान एक आदिवासी बेटी के साथ हुए गैंगरेप रेप और देह व्यापार के आरोपी को भाजपा कि सरकार ने पहले बचाया फिर छत्तीसगढ़ भाजपा ने उसे भानुप्रतापपुर के चुनाव में उम्मीदवार बनाया था।

रेप पीड़िता की नहीं हो रही सुनवाईः नारायण चंदेल

रायपुर। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मंत्री मो. अकबर के निर्वाचन क्षेत्र कवर्धा के मुस्लिम युवक द्वारा दुष्कर्म करने के मामले में पांडातराई पुलिस के रवैये पर सवाल किया है कि बिना राजसंरक्षण के यह कैसे मुमकिन है। आज मजबूर

होकर पीड़िता ने थाने पहुंचकर आत्मदाह करने का प्रयास किया है। पीड़िता का स्पष्ट आरोप है कि दुष्कर्म के इस मामले में पुलिस जानबूझकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रही है। मंत्री अकबर ने अब तक न तो घटना पर संज्ञान लिया है और न पुलिस द्वारा कोई उचित और ठोस कार्यवाही हुई है और न पीड़िता को आरंभिक न्याय मिला है। मंत्री अकबर अपनी भूमिका स्पष्ट करें। भूपेश बघेल सरकार के लचर कानून व्यवस्था के कारनामे पौने पांच साल में लगातार सामने आते रहे हैं और अब ताजा बानगी सामने आई है कि दुष्कर्म पीड़िता को अपने साथ होटल में दो दिन दुष्कर्म, मारपीट करने और पुलिस द्वारा शिकायत सुनने की बजाय अकेले में मिलने कहे जाने की दास्तान राजधानी के प्रेस क्लब आकर मीडिया के सामने बयान करना पड़ी। पीड़िता अपने साथ घटी वारदात की शिकायत दर्ज कराने पांडातराई थाने पहुंची तो थानेदार ने उससे अकेले में मिलने कहा। भूपेश बघेल सरकार की तुष्टिकरण की भूख छत्तीसगढ़ को संघर्ष की आग में झोंक रही है। खुलेआम लव जेहाद चल रहा है।

एक तो सीएम का परफॉर्मेंस खराब, दूसरा विधायक कौन? : विजय

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा सांसद विजय बघेल ने मुख्यमंत्री द्वारा कांग्रेस के दो विधायकों का परफॉर्मेंस खराब होना बताये जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि जिन दो कांग्रेस विधायक का प्रदर्शन खराब है, उनमें से एक तो स्वयं भूपेश बघेल हैं, दूसरा कौन है, यह उन्हें लगे हाथ स्पष्ट कर देना

चाहिए। क्या वह विधायक भूपेश बघेल के नए नवेले उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव हैं या जिनसे कृषि विभाग छीन लिया गया, वे रविन्द्र चौबे हैं अथवा जिनके गृहमंत्री रहते छत्तीसगढ़ में कोई महिला सुरक्षित नहीं है, वे ताम्रध्वज साहू इस द्विसदस्यीय पैनल में शामिल हैं। यदि नहीं, तो क्या जनता का राशन ठिकाने लगवा देने वाले खाद्यमंत्री भगत, बेरोजगारों के आंकड़ों में फर्जीवाड़ा कराने वाले खेल युवा मंत्री पटेल, जल जीवन मिशन को बर्बाद करने का ठेका लिए बैठे पीएचई मंत्री गुरु या नगरनिगमों को कांग्रेस की जागीर बना देने वाले नगरीय प्रशासन मंत्री डहरिया या फिर जिनके विभाग में 2 हजार करोड़ का शराब घोटाला हो गया, वे कवासी लखमा या जिनकी सरपरस्ती में तुष्टिकरण चल रहा है, वे अकबर या जिनकी जमीन पर मदिरा दुकान खुली, वे महिला बाल विकास मंत्री भेड़िया अथवा मुख्यमंत्री की प्रियपात्र अफसर को भ्रष्ट बताने वाले जयसिंह में से कोई एक भूपेश बघेल के साथ इस सूची में शामिल है,दुर्ग सांसद विजय बघेल जी ने भूपेश बघेल को याद दिलाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान आपने अपने मंत्री और विधायकों को अपने क्षेत्र में हारने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी।

भाजपा झूठ का पुलिंदा हैः अनीता योगेंद्र शर्मा

रायपुर। धरसींवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ग्राम पंचायत मांढर में 500

कांग्रेसियों ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की बात कर रहे हैं।मैं पूछना चाहती हूं कि कांग्रेसियों की लिस्ट जारी कर दे जिस कार्यक्रम में 200 लोग नहीं आए वह इस तरह से झूठ और अफवाह फैला रहे हैं। इसी झूठ का नतीजा है कि आज 14 सीटों में सिमट के रह गए आने समय में अगर यही हाल रहा तो 14 सीटों के लायक भी नहीं बचेंगे।विधायक अनीता शर्मा ने कहा कि धरसीवा की जनता नहीं पूरे प्रदेश में भाजपा का सूपड़ा साफ हो रहा है।

आयुष पाण्डेय सोशल मीडिया के राष्ट्रीय कोर्डिनेटर बनाये गये

रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस के सोशल मीडिया और डिजिटल

प्लेटफार्म के पदाधिकारियों की नियुक्ति की गयी है। जिसमें रायपुर छत्तीसगढ़ के आयुष पाण्डेय को राष्ट्रीय कोर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। आयुष पाण्डेय इसके पहले सोशल मीडिया के राष्ट्रीय सह समन्वयक थे तथा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रमुख अंग है।

न्याय कानून किताबों तक सीमित नहींः शर्मा

रायपुर। माननीय उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के कार्यपालक अध्यक्ष तथा माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय के न्याय मूर्ति माननीय श्री गौतम भादुड़ी जी के निर्देशानुसार तथा माननीय श्री संतोष शर्मा, जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर एवं जिला महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में इस वर्ष की प्रथम किशोर न्याय (बालकों के देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों

का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं बाल अधिकार पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के सभाकक्ष में एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता श्रीमती अपूर्वा दांगी, प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड रायपुर द्वारा की गई। जिसमें प्रधान मजिस्ट्रेट श्रीमती अपूर्वा दांगी ने किशोर न्याय अधिनियम की पूरी प्रक्रियाओं को सरल एवं सहज रूप से वर्णन किया। किशोर न्याय अधिनियम के संबंध में विभिन्न विभागों से सामंजस्य स्थापित करते हुये हर उस बालक तक न्याय पहुंचाने की बात कही। चिकित्सा विभाग से वरिष्ट डॉ. प्रीति ने यह बताया कि यदि बच्चों के साथ कोई लैंगिक अपराध घटित हो और जिसके कारण गर्भाधारण हो जाता है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश और कानूनों के प्रावधानों के तहत कैसे कार्यवाही की जाती है के बारे में विस्तृत रूप से बताया। किशोरों का मेडिकल परीक्षण और स्वास्थ्य परीक्षण किस प्रकार किया जाता है यह जानकारी दी गई। श्रीमती निशा मिश्रा जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह बताया गया कि. उनका विभाग किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के पालन में समग्र रूप से कार्य कर रहा है और अधिक से अधिक बच्चों से जुड़े पुनर्वास जैसे प्रकरणों के निराकरण में सहयोग कर रहा है।

पॉवर कंपनी में मुख्य अभियंता सिन्हा की भावभीनी विदाई

सहायक प्रबंधक श्री राव एवं अनुभाग अधिकारी श्री नायक भी हुये सेवानिवृत्त

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी से सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता (सी.एण्ड आर.ए.) श्री अजय कुमार सिन्हा को कंपनी मुख्यालय विद्युत सेवाभवन में भावभीनी विदाई दी गई। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एमडी श्री मनोज खरे एवं जनरेशन कंपनी के एमडी श्री एस.के.कटियार ने उन्हें प्रमाण पत्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। प्रबंध निदेशकों ने श्री सिन्हा की उत्कृष्ट कार्यशैली और सहज व्यवहार की प्रशंसा की। इस अवसर पर सेवानिवृत्त सीई श्री सिन्हा ने अपने कार्य अनुभव बताते हुए अपनी सफलता का श्रेय टीमवर्क को दिया तथा सेवायात्रा के दौरान अधिकारी-कर्मचारियों से मिले सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया।

इसी प्रकार अन्य कार्यक्रमों में जनरेशन कंपनी के वित्त विभाग में सहायक प्रबंधक श्री बी.वेंकट राव एवं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के मानव संसाधन विभाग में अनुभाग अधिकारी श्री लोचनप्रसाद नायक को भी भावभीनी विदाई दी गई।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.